ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

जुलाई : 2004

मूल्य : 7 रुपये

साझा न्यूनतम कार्यक्रम

नई सहस्त्राब्दी में संयुक्त वन प्रबंधः कुछ मुद्दे

वैज्ञानिक उद्यमियों के माध्यम से विश्वस्तरीय उत्कृष्टता

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति 2004-05

प्यासे प्रायद्वीप को जल-दान

जनसंख्या विस्फोट का दुष्चक्रःकारण और निवारण

शुक्र ग्रह का पारगमन

वन महोत्सव

वृहस्पतिवार 10 जून, 2004 को नई दिल्ली में कुतुब मीनार से ओलम्पिक मशाल रिले- 2004 के शुभारंभ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कल्माड़ी को ओलम्पिक मशाल थमाते हुए।

योजना

वर्ष : 48 अंक 4 जुलाई, 2004 आषाढ़–श्रावण, शक–संवत् 1926

प्रधान संपादक – **महादेव पकरासी**

संपादक – **राजेन्द्र राय**

सहायक संपादक – **स्नेह राय**

उप संपादक – **रेमी कुमारी**

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2566
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – **दीपायन मैत्रा**

इस अंक में

• साझा न्यूनतम कार्यक्रम	अतुल कौशिश	5
• नई सहस्त्राब्दी में संयुक्त वन प्रबंध : कुछ मुद्दे	पी. के. सक्सेना	9
• वैज्ञानिक उद्यमियों के माध्यम से विश्वस्तरीय उत्कृष्टता	किरण मजूमदार शाह	17
• भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण नीति 2004–2005	जी. श्रीनिवासन	22
• प्यासे प्रायद्वीप को जल दान	अरविंद घोष	26
• जनसंख्या विस्फोट का दुष्चक्र : कारण और निवारण	सुकन पासवान प्रज्ञाचक्षु	31
• भारतीय कृषि का मूलाधार – मानसून पवन	राधाकांत भारती	35
• विज्ञान – शुक्र ग्रह का पारगमन	शैलेन्द्र मोहन कुमार	36
• ज्ञान–सागर	सरिता कुमारी	39
• मंथन – सफलता–असफलता	ज़ियाउर रहमान जाफ़री	41
• जहां चाह, वहां राह – हौसले बुलंद हो तो अड़चने बाधा नहीं बनती	बबीता रानी जायसवाल	44
• स्वास्थ्य चर्चा	–	47
• नए प्रकाशन	–	50

योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; द्विवार्षिक : 135 रु.; त्रैवार्षिक : 190 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

पूरे विश्व में आज पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरणीय समस्याओं की खूब चर्चा हो रही है। पर्यावरण की स्थिरता में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण, विकास और प्रबंध अनिवार्य है। वनों से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। लेकिन आज लगातार वन कट रहे हैं एवं उनके संसाधनों का अनावश्यक दोहन हो रहा है। जरूरत से ज्यादा दोहन तथा अन्य मानव विकास गतिविधियों की वजह से वनों का निरंतर क्षरण हुआ है और उत्पादकता भी घटी है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1988 में एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई एवं पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1 जून, 1990 को एक संयुक्त वन प्रबंध पारित किया जिसमें वनों के संरक्षण तथा अवक्रमित वन भूमि के विकास में वनों के समीप रहने वाले ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी की बात कही गई थी।

1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर इस अंक में विशेष लेख शामिल किया गया है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए जब तक ग्रामीण भारत का उदय नहीं होता तब तक भारत उदय की बात बेमानी है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी को दूर करना जरूरी है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार अगले तीन महीने में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करेगी। इस बार सरकार की साझा न्यूनतम कार्यक्रम की जानकारी भी पाठकों को दी जा रही है।

अंक में 12 मई, 2004 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक उद्यमियों के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय उत्कृष्टता प्राप्त करने के बारे में छठे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर बायोकॉन ग्रुप की मुख्य प्रबंध निदेशक पद्मश्री श्रीमती किरण मजूमदार शाह के अभिभाषण को भी शामिल किया गया है। उम्मीद है पाठकों को यह रुचिकर लगेगा।

इस अंक में पाठकों को भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीतियों की भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटो का विशाल इलाका सूखे बराबर त्रस्त रहता है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने इन इलाकों तक पानी पहुंचाने की एक अंतर्जलीय सम्पर्क परियोजना तैयार की है। इस परियोजना की विस्तृत जानकारी 'प्यासे प्रायद्वीप को जल–दान' नामक लेख में मिलेगी।

11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर अंक में जनसंख्या विस्फोट, कारण एवं इसके निवारण की चर्चा है।

खगोल के इतिहास में 8 जून, 2004 एक अविस्मरणीय दिन रहेगा। उस दिन शुक्र ग्रह ने सूर्य के सामने से 122 वर्ष के बाद पारगमन किया। इस रोचक और महत्वपूर्ण घटना की दिलचस्प गाथा पाठक 'विज्ञान' स्तंभ के तहत पढ़ सकेंगे।

अंक में अन्य नियमित स्तंभ भी शामिल हैं। आशा है पाठकों को अंक पसंद आएगा।

आपकी राय

(संदर्भित अंक–अप्रैल, 2004)

'ज्ञान सागर' शुरू करने पर धन्यवाद

अप्रैल 2004 अंक खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को समर्पित है। यह अंक अद्वितीय है। इसमें खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का लेख अति सुन्दर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में दी गई जानकारी पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी 'ज्ञान सागर' नामक नया कॉलम शुरू करके आपने युवा पाठकों के आग्रह को स्वीकार करके बहुत सराहनीय प्रयास किया है। स्वास्थ्य चर्चा के अन्तर्गत 'मानसिक तनाव – एक जैविक रासायनिक रोग' के कारण, निवारण के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लगी। 'हस्तशिल्प का खजाना : भारत' नामक लेख में भारत के प्रमुख हस्तशिल्प के बारे में बताया गया है। हस्तशल्पि उद्योग को भारत सरकार सहायता उपलब्ध कराती रहें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसका लोप हो जाएगा। अंक जानकारी से परिपूर्ण रहा।

सुनील कुमार सेठी
अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश)

'योजना' को शुभकामनाएं

सबसे पहले मैं 'योजना' के संपादक, प्रकाशक एवं लेखकों को ज्ञानवर्द्धक जानकारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। अप्रैल के अंक में बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी व इसके दुष्परिणाम एवं ऐहतियात के बारे में जानकारी काफी अच्छा लगा। 'योजना' पत्रिका को मेरी शुभकामनाएं तथा मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह पूर्ण और सटीक जानकारी देंगे।

कुमार सोनू
पूर्वा, हाजीपुर (वैशाली)

लेखकों का परिचय दें

'योजना' में प्रकाशित होने वाला हर लेख अति सारगर्भित और ज्ञानवर्द्धक होता है। लेकिन जब योजना खोलते ही हम युवाओं के आदर्श महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का लेख हो तो इसे हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं। निश्चय ही यह लेख भी उनके भविष्यदृष्टा और स्वप्न दृष्टा व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, लेकिन अभी तक सरकार के सिद्धान्त रूप से किसी योजना (पूरी योजना) को स्वीकार करने और क्रियान्वित करने में हमेशा ही अंतर दिखा है।

योजना के सदैव नवीनीकृत विषयवस्तु की तारीफ करना आवश्यक है। इस अंक में प्रकाशित 'मंथन' और 'ज्ञान–सागर' निश्चय ही पत्रिका के गंभीर वातावरण को तोड़ यथार्थ के धरातल पर तो अति है। कृपया मंथन में लिखने वाले सम्माननीय लेखकों का भी परिचय दिया करें। इस अंक में प्रकाशित 'तुम्हारा धर्म' में लिखी कविता 'जब जीवन ही है संघर्ष' अति विचारोत्तेजक थी। बहुत पसंद आई। एक और विनती है, कृपया संपादकीय लिखने वाले संपादक का नाम या हस्ताक्षर नीचे दिया करें। परम्परागत रूप से सही रहेगा।

'रंगनाथ'
बी.एच.यू., वाराणसी

आर्थिक पहलू की विशिष्ट जानकारी

अंक में प्रकाशित सभी आलेख अपने–आप में महत्व रखते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा जो भाषण के अंश ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं परिपृष्ट पर प्रकाशित किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्तरोत्तर विकास हेतु बिन्दुवार दर्शाया गया है, यह जनमानस में अपनी अलग छाप छोड़ती है। संजय वर्मा का आलेख 'बर्ड फ्लू बना नई आपदा' – में एक ओर मानव के स्वास्थ्य प्रभाव पर विश्लेषण किया गया वहीं दूसरी ओर पक्षियों को खासकर मुर्गों को नष्ट किए जाने से एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को आर्थिक दंश झेलना पड़ रहा है जिसके लिए जिम्मेवार कौन है यह प्रश्नचिह्न बना है। वृहत् एवं नवीन जानकारी हेतु प्रकाशित लेखों के लिए प्रकाशक, लेखकों एवं संपादक को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं आशा व विश्वास रखता हूं कि आगामी अंक में भी अच्छे–अच्छे लेख प्रकाशित होंगे।

डा. शिशिर कुमार सिंह
वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय,
गोड्डा (झारखंड)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

ईमानदारी बरतें

खाद्य सुरक्षा विशेषांक पढ़ा। भारत आजादी के 57 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। अनाज मंगाने वाला भारत आज अनाज निर्यात कर रहा है। देश में इतना अनाज उत्पादित हो रहा है कि रखने को स्थान की कमी हो गई है। प्रति व्यक्ति अन्न उपलब्धता 390 ग्राम से बढ़ कर 500 ग्राम हो गई है, इस पर से दूसरी हरति क्रांति की तैयारी हो रही है। निश्चय ही इस तरह की खबरें 1.2 अरब लोगों को फीलगुड कराने के लिए काफी हैं। लेकिन देश के विभिन्न भागों से रह–रहकर आती भुखमरी की खबरें इन सारी उपलब्धियों को सिरे से खारिज करती प्रतीत होती हैं। एक तरफ अन्न भंडार के कीर्तिमान तो दूसरी तरफ भुखमरी की खबरें एक अजीब विरोधाभासी चित्र प्रस्तुत करती हैं। अंत्योदय योजना, मीड डे मील योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं के बावजूद खाद्य सुरक्षा की स्थिति नहीं आना पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा करता है। बड़े–बड़े आंकड़ों की सार्थकता तभी होगी जब जरूरतमंद लोग इसके लाभार्थी बनेंगे। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा तभी संपुष्ट होगी जब हमारा तंत्र इसमें ईमानदारी से दिलचस्पी लेगा।

रोहित कुमार सिंह
सी–12, पत्रकार नगर, कंकड़बाग,
पटना–20 (बिहार)

IAS/PCS MAINS/PT MAINS-CUM-PT

वर्ष 2003 सिविल सेवा में *DISCOVERY* की रणनीति का प्रतिबिम्बन करने वाले सफल अभ्यर्थी

सामान्य अध्ययन पर कम ध्यान दिये जाने से सफलता संदिग्ध हो सकती है, जिसकी प्रामाणिकता वर्ष 2003 की मुख्य परीक्षा के परिणाम हैं। इस परिणाम ने सामान्य अध्ययन की नये दृष्टिकोण के साथ तैयारी की रणनीति को अनिवार्य बना दिया है। निश्चित रूप से एक वैकल्पिक विषय की अपेक्षा सामान्य अध्ययन की महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस आलोक में ***DISCOVERY*** के "सुधार आधारित विकास कार्यक्रम" की लक्षित एवं तार्किक रणनीति सफलता की पथ प्रदर्शक बन सकती है–

पंकज गुप्ता 002257

संजीव कुमार सिंह 033413

सचिन बादशाह 296030

सुनील कु० अग्रवाल 168599

सामान्य अध्ययन

—सी.बी.पी. श्रीवास्तव, अख्तर मलिक, अनिल केशरी एवं अन्य

वर्ष 2003 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से निम्नांकित प्रश्न सी.बी.पी. श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा में ही चर्चा में लाए गए थे।

प्रथम पत्र प्र.सं. 4. क, ग, 5. I,V, 6. क, ख, 7. क, ख, 8. क, ख, ग, 9. ख, ग, घ, 10. क, 11. क, ग 13. क, ख,

द्वितीय पत्र प्र.सं. 1. क, ख, ग, 2. क, ख, 3. क, ख, ग, 4. क, ख, 5. क, ख, ग, 6. क, ख, ग, च, य, ट, ठ, ढ़, ण 7. ग, 10. क, ग, 12. ग, ड़, ii, iii

इतिहास
— डॉ० हरिश्चन्द्र वर्मा, डॉ० लालबहादुर वर्मा एवं अख्तर मलिक

समाजशास्त्र
—सी.बी.पी. श्रीवास्तव

हिन्दी साहित्य
प्रख्यात प्राध्यापक (पटना)
तकनीकी कारणवश नाम का प्रकाशन सम्भव नहीं है।

दर्शनशास्त्र
—अविनाश तिवारी एवं टीम, निष्ठा (इलाहाबाद)

लोक प्रशासन
—दिवाकर गुप्ता

विधि
– विकाश सिंह एवं विशेषज्ञ दल
(लोक, न्यायिक एवं अभियोजन अधिकारी परीक्षा)

निबंध
— डॉ० लालबहादुर वर्मा, सी.बी.पी. श्रीवास्तव एवं अनिल केशरी

नियमित कक्षा के लिए नामांकन प्रारंभ

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के पश्चात मुख्य परीक्षा के लिए दूसरा बैच प्रारम्भ

DISCOVERY
...Discover your mettle
(THE IAS ACADEMY BY- C.B.P. SRIVASTAVA)
B-14 (Basement), Commercial Complex, Beside HDFC Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-9

30906050
☎ 33058532
27655891

साझा न्यूनतम कार्यक्रम

○ अतुल कौशिश

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम से अगर कुछ दिलचस्पी उत्पन्न हुई है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि इस कार्यक्रम में देश के लोगों को, खासकर उस वर्ग को जो हाल के दिनों में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, को आश्वासन देने की कोशिश की गई है।

यह तो मानता ही पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में आए उछाल से देश का एक विशाल वर्ग अछूता रह गया है। लेकिन यह वर्ग सरकार से चाहता क्या है? संक्षेप में कहें तो यह लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों, समान अवसरों और सामाजिक सदभाव की ही अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम से अगर कुछ दिलचस्पी उत्पन्न हुई है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि इस कार्यक्रम में देश के लोगों को, खासकर उस वर्ग को जो हाल के दिनों में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, को आश्वासन देने की कोशिश की गई है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम को नीति निर्माण और प्रशासन के आधार के रूप में देखा जा सकता है और शायद यह अधिकांश सवालों के जवाब भी दे सकता है। लेकिन 5700 शब्दों के इस दस्तावेज का महत्व भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके बिना, चाहे अमीर और ताकतवर देश ही क्यों न हो अपने आप को विकसित नहीं कह सकता। सरकार ने प्रशासन के जिन छह बुनियादी सिद्धान्तों पर अमल करने का वायदा किया है उनका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में कम समृद्ध वर्गों के हालात सुधारना है और ये वर्ग देश में असंगठित क्षेत्र की एक बड़ी ताकत माने जाते हैं।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम की ओर काफी ध्यान आकर्षित हुआ है जिसका कारण यह है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और खेतिहर पैदावार में अधिक निवेश करने का इरादा व्यक्त किया गया है। शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सभी करों पर 2 प्रतिशत तक अधिभार लगाने का एक प्रस्ताव है। वैसे तो, बेहतर शिक्षा और सर्वसुलभ शिक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपये की जरूरत होगी। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से को शिक्षा के लिए निर्धारित करने की सराहना की जानी चाहिए। इसमें से आधा पैसा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

बेरोजगारी देश की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार तत्काल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लाए जो हरेक ग्रामीण, शहरी गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवार में कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को हर साल कम से कम 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कानूनी गारंटी, यानी काम का अधिकार प्रदान करे। इस बीच काम के बदले अनाज का एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम भारत की तस्वीर ही बदल सकते हैं। लेकिन काम बहुत भारी है। क्योंकि लगभग 10 करोड़ बेरोजगार ग्रामीण मजदूरों के लिए ही 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्वतंत्र विदेश नीति पर अमल करने की बात कही गई है। इस नीति में देश की पुरानी परंपरा को ध्यान में रखने और विश्व संबंधों में बहु–ध्रुवीयता को बढ़ावा देने तथा एकपक्षीयता की दिशा में की जाने वाली हर कोशिश का विरोध करने पर जोर दिया गया है। हाल ही में देश में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत की

ISGS
Indian School of General Studies

IAS / PCS प्रवेश सूचना

ALS

सामान्य अध्ययन
(हिन्दी माध्यम)

6 2005-06 की परीक्षा हेतु विशेष रूप से तैयार की गयी Prelim-cum-Main GS Foundation Package जुलाई *2004* से प्रारंभ होगी।

कुल सीट- 75, कोर्स की अवधि: 5 महीने (06 July 2004 - 31 December 2004)

हिन्दी माध्यम GS की सिविल सेवा ट्रेनिंग के इतिहास में अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम

हमारी योजना

- कोर्स के प्रारंभ में GS Basics की जानकारी
- 450 घंटे क्लासरूम प्रशिक्षण
- पूरे तीन दिनों का परिवर्तनकारी वर्कशॉप
- पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री
- निबंध लेखन अभ्यास
- निरन्तर परीक्षण (Test) व्यवस्था
- 30 Tests (PRELIM), 15 Tests (MAIN) (6 July - 31 December, 2004 तक)
- 31 दिसंबर से 20 अप्रैल तक प्रत्येक सप्ताह दो टेस्ट की व्यवस्था

GS Programme Director **Manoj K. Singh**
Director- ALS, Y D Misra's IAS, Interactions, ISGS, MIPS Education, Managing Director-Competition Wizard

Special Concession for SC/ST Candidates

कार्यशाला सामान्य अध्ययन "तैयारी कैसे करें"
द्वारा **JOJO MATHEWS**
JUNE 25, 2004 (11:00 AM)

Magic Moments
IAS-PCS Workshop हिन्दी माध्यम
3 Days with **SHASHANK ATOM**
JULY 6, 7, 8, 2004 (9:00 AM - 6:00 PM)

LATE ENTRY WILL NOT BE PERMITTED

STALWARTS COMBINE TO FORM THE BEST EVER TEAM IN GS

इतिहास व संस्कृति
Y D Misra
&
Manoj K Singh *(Director-ALS, YD Misra's IAS, Interactions, MIPS Education, ISGS, Managing Director-Competition Wizard)*

भूगोल
Shashank Atom *(Director-ALS, Interactions, MIPS Education, Chief Editor-Competition Wizard)*, **Jojo Mathews** *(Director-ALS, Interactions, MIPS Education, Managing Editor- Competition Wizard)* **& Other experts**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सांख्यिकी
Jojo Mathews & Other experts

निबंध एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे
Shashank Atom

भारतीय राजव्यवस्था
Manoj K Singh & Manoj Somvanshi

भारतीय अर्थव्यवस्था
P K Jha & Other experts

समसामयिकी
Jojo Mathews, A Jha & S P Jha

मानसिक योग्यता व सामान्य विज्ञान
A K Singh, Vijay Kumar & Other experts

AT INDIAN SCHOOL OF GENERAL STUDIES

Corporate Office: ALTERNATIVE LEARNING SYSTEMS (P) LTD
B-19, ALS House, Near UTI ATM, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9 **Ph: 27652738, 27651700, 27651110, 9810345023**

Divisions of ALS

ISGS Indian School of General Studies | interactions | MIPS EDUCATION | COMPETITION WIZARD | NH

विदेश नीति में पारंपरिक स्वतंत्र सोच की उपेक्षा की जा रही थी। जबकि इस सोच से देश का भला ही हुआ था। लेकिन रक्षा के मामले में कोई ढील नहीं होगी। अपने परमाणु पड़ोसियों के साथ परस्पर विश्वास बनाने की दिशा में स्पष्ट और यथार्थ उपायों पर अमल करने के साथ–साथ एक विश्वसनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम भी बनाए रखा जाएगा।

इन दिनों घरेलू परिदृश्य में जो तनाव उभर कर आए हैं, उन्हें साझा न्यूनतम कार्यक्रम में निर्दिष्ट कई उपायों के जरिए दूर किया जाएगा। पोटा समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आतंकवाद से लड़ने का इरादा मजबूत बना रहेगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल 15 दलों ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, उसकी रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के साथ–साथ देश के सामाजिक ताने–बाने को बिगाड़ने वाले सभी कट्टरपंथी और रुढ़िवादी तत्वों से कड़ाई से निपटने का संकल्प व्यक्त किया है। सरकार साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून लागू करेगी और उस कानून पर अमल करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। देश को ध्यान रखना होगा कि बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उसके संकल्प में कमजोरी के किसी भी प्रकार के आभास को बड़ी तेजी से दूर किया जाए। इस दृष्टि से साझा न्यूनतम कार्यक्रम एकदम प्रासांगिक हो जाता है।

कम से कम 7 से 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर की चर्चा के साथ–साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस दर को इस प्रकार हासिल किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार के लिए एक सुरक्षित और व्यावहारिक आजीविका सुनिश्चित हो सके। महिलाएं, जिनमें से अधिकांश को घरों में और कार्यस्थलों पर अक्सर शोषण का सामना करना पड़ता है, वे भी अब पूर्ण अधिकारिता की उम्मीद कर सकती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रयास यह होगा कि पंचायतों को गरीबी दूर करने और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर अमल करने का एक कारगर माध्यम बनाया जाए। अगर राज्य सरकार सहमत हों, तो पंचायतों को सीधा धन भेजा जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा, पंचायती राज के आधार के रूप में सशक्त होकर उभरे।

जब तक ग्रामीण भारत का उदय नहीं होता तब तक भारत उदय की बात बेमानी है और इसके लिए ग्रामीण बेरोजगारी और भूख को, अगर एकदम दूर करना संभव नहीं है, तो उसे कम से कम करना ही होगा। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार अगले तीन महीने में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए एक व्यापक मध्यावधि रणनीति प्रस्तुत करेगी और अगर यह व्यावहारिक सिद्ध हुई तो सरकार सर्वसुलभ खाद्य सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर किया जाएगा ताकि असहाय और अशक्तों तक अनाज पहुंचाने के लिए विशेष योजनाओं पर अमल किया जा सके। इसके अलावा खाद्यान्न की कमी वाले इलाकों में खाद्यान्न बैंकों की स्थापना की जाएगी।

खेतिहर पैदावार में आए ठहराव को देखते हुए सिंचाई सुविधाओं के दायरे को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। भारत में 14 करोड़ हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता है, लेकिन सिंचाई सुविधाएं केवल 6.5 करोड़ हेक्टेयर तक ही पहुंच पा रही हैं। खेती में सार्वजनिक निवेश, हाल के वर्षों में घटकर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सशक्त पंचायती राज प्रणाली, गांव में रहने वाले भारत में नई आशा का संचार कर सकती है और इससे कृषि क्षेत्र के उत्थान में भारी मदद मिल सकती है। पंचायतों की मदद से शुरू किए गए सुधारों के सफल होने की भारी संभावना है क्योंकि सीधा निवेश करने वाले पैसा खर्च करते समय काफी सावधानी बरतते हैं।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में न केवल उद्यमियों और व्यापारियों की, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा सभी व्यावसायिकों तथा समाज की उत्पादक ताकतों की रचनात्मक शक्तियों को बढ़ावा देने के बारे में किए गए वायदों से इन अटकलों को विराम लग जाना चाहिए कि नई सरकार व्यापारिक समुदाय के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण रवैया शायद न अपनाए।

जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपनी पारी की शुरुआत की, तब कुछ वर्गों ने अटकलें लगाई थी कि शायद यह सरकार आर्थिक सुधारों के प्रति अधिक उत्साहित नहीं होगी, लेकिन साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इन सुधारों के प्रति दृढ़ संकल्प को दोहराया गया है। लेकिन इसके साथ इतना जरूर कहा गया है कि ये सुधार मानवीय चेहरे के साथ होने चाहिए। मानवीय चेहरे की शब्दावली का हवाला प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह देते आए हैं और काफी पहले, 1990 के दशक के शुरुआत में भारत में आर्थिक सुधार शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सुधार ऐसे होने चाहिए जिनसे प्रगति हो, निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर अधिक संख्या में पैदा हों। जैसा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के

आर्थिक सुधारों का आधार मूलतः गांवों की खुशहाली को फैलाना और उसे मजबूत करना, सार्वजनिक प्रणालियों और जनसेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करना, देश के आम नागरिक के जीवन स्तर में स्पष्ट और ठोस सुधार लाना होगा।

नई सरकार की श्रम नीति में श्रमिक कानूनों में कुछ सुधारों की जरूरत को स्वीकार किया गया है। लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों को नौकरी पर रखना और जरूरत खत्म होते ही उन्हें तत्काल नौकरी से निकाल देने की अवधारणा को नामंजूर किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो श्रमिक कानून, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देते हैं उन पर फिर से गौर करना जरूरी है। इसी प्रकार सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण की नीति को जारी रखेगी लेकिन इसे लाभ कमाने वाली कंपनियों पर लागू नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि कोई भी देश अपने जेवरात बेचकर अपने घर का खर्च नहीं चलाता है। लेकिन साझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाइयों की मदद नहीं की जाएगी जिनसे एकाधिकार उत्पन्न होता हो और जितनी वजह से प्रतिस्पर्धा मे रुकावट आती हो। निजीकरण और सामाजिक जरूरतों के बीच सीधा संपर्क होना बहुत जरूरी है।

निजीकरण और उदारीकरण के कट्टर समर्थकों को ऐसी सरकार के आने से निराशा नहीं होनी चाहिए, जो सत्ता में बने रहने के लिए काफी हद तक वामपंथियों पर निर्भर हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दानी रोडरिक ने कहा है कि "बड़े पैमाने पर उदारीकरण से किसी देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे तो उद्यमशीलता को नुकसान पहुंचेगा। नीतियों में जिन सुधारों से उद्यमियों के आधार को पूरी तरह से बदले बिना, इसके लिए मार्ग प्रशस्त होता हो, ऐसे सुधार अधिक सफल सिद्ध हो सकते हैं।" अगर यह सच है कि भारत बड़ी तेजी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है तो इसका काफी हद तक श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने भारत को उसके जबर्दस्त कर्ज के संकट से उबारने और कड़े आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए पिछली सरकार में अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया था। इसलिए आलोचकों को डा. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व में साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदों को नजरअंदाज करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ❑

(सौजन्यः पत्र सूचना कार्यालय)

(श्री अतुल कौशिश स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

IAS 2004-05

दर्शनशास्त्र

(हिन्दी & ENGLISH MEDIUM)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय व जयपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ विद्वानों व डॉ. एस पी झा के द्वारा

Course Coordinator डॉ. एस पी झा

- स्नातकोत्तर- स्वर्णपदक प्राप्त (B.H.U.)
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त
- दर्शनशास्त्र के अध्यापन का विश्वसनीय अनुभव
- अनेक पुस्तकों के लेखक
- भारतीय दर्शन परिषद की छात्रवृत्ति प्राप्त
- पातंजल योग संस्थान लंदन के उपाध्यक्ष

FEES: Rs 4500/-

(50% Fees Students' Scholarships ALS द्वारा प्रायोजित)

Batches begin: 10 JULY, 2004

MIPS Education

Corporate Office: B-19, ALS House, Near UTI ATM, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9

Ph: 27651700, 27651110, 27652738

नई सहस्त्राब्दी में संयुक्त वन प्रबंध : कुछ मुद्दे

○ पी. के. सक्सेना

संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम पर कारगर ढंग से अमल करने से देहातों में ग्रामीणों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में काफी मदद मिलेगी, गरीबी कम होगी, और परिणामस्वरूप आमदनी तथा रोजगार के उच्च स्तर प्राप्त किए जा सकेंगे।

वनों की पर्यावरण की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इनसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में काफी तेजी आती है। स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण, विकास और प्रबंध अनिवार्य होता है। वनों तथा निकटवर्ती भूमि के क्षरण के लिए लोगों की भागीदारी की कमी और संसाधनों के इस्तेमाल की किसी नियामक प्रणाली का न होना, काफी हद तक जिम्मेदार है। सौ से भी अधिक वर्षों से विकास तथा अमल में लाई जा रही वन प्रबंध प्रणालियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में बनाए नहीं रखा जा सका है। सार्वजनिक दृष्टि से जरूरत से ज्यादा दोहन तथा अन्य मानव विकास गतिविधियों की वजह से, ये प्रणालियां असरदार नहीं रह गई हैं। नतीजा यह हुआ कि वनों का निरंतर क्षरण हुआ है और उत्पादकता घटी है, जिसकी वजह से एक दुष्चक्र बन गए है और इससे वन संसाधन छीजते चले गए हैं। इसने ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों में गरीबी की पुरानी समस्या को और भी गंभीर बना दिया है।

अब, यह आमतौर से माना जाने लगा है कि वनों के तथा उनके आसपास रहने वाले ग्रामीण तथा जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही वनों के संरक्षण, वनारोपण, विकास तथा प्रबंध गतिविधियों को सफल बनाया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में प्राकृतिक वनरोपण, जैव–विविधता के संरक्षण और स्थानीय लोगों को अनुकूल प्रबंध पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया गया था। वनों तथा पर्यावरण के संरक्षण और ग्रामीणों की निर्धनता स्तर घटाने की बुनियादी नीति बनाने और उस पर अमल करने के परिणामस्वरूप ही नब्बे के दशक में संयुक्त वन प्रबंध योजना का मार्ग प्रशस्त हुआ। विविधतापूर्ण सांस्कृतिक और जातीय व्यवस्था को सामाजिक– आर्थिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ दिया गया जिससे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के व्यावहारिक उपयोग के जरिए उत्पादकता और समृद्धि का मार्ग आसान हुआ।

वनों की पर्यावरण की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका है

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1 जून, 1990 को एक संयुक्त वन प्रबंध प्रस्ताव पारित किया जिसमें वनों के संरक्षण तथा अवक्रमित वन भूमि के विकास में वनों के समीप रहने वाले ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी :

- स्वयंसेवी एजेंसी, गैर–सरकारी संगठन,

ADMISSION OPEN
FROM 31st MAY

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:
* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Mains Special for UPSC Mains-04.

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)
MAINS - 2500/-**
MAINS + PRE. - 3500/-**
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

***UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी**

NEXT BATCH STARTS AFTER UPSC (PRELIMS) RESULT

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Director - Alok Lall

*** 1 April से प्रभावी*

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN COMMERCIAL COMPLEX, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005

At Allahabad : "INSEARCH", Opp. D.J. Hostel, Near Anand Bhawan. Ph.: 0532-2467708

व्यक्ति नहीं बल्कि ग्रामीण समुदाय (लाभार्थी और राज्य वन विभाग के बीच तालमेल से कार्यक्रम पर अमल)

- लाभार्थियों या स्वयंसेवी एजेंसी, गैर–सरकारी संगठन को भूमि पर स्थायित्व या पटटे के कोई अधिकार नहीं। लाभार्थियों के वन भूमि के उपयोग को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकार।
- लाभार्थियों को घास, पेड़ों की टूटने वाली शाखाओं और टहनियों और गौण वनोपज जैसे उपयोग अधिकार दिए जाने चाहिए। वृक्षों की अंतिम पैदावार में प्रतिशत हिस्से का आधार वनों के सफल संरक्षण और राज्य सरकार हिस्से का आधार वनों के सफल संरक्षण और राज्य द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- वन भूमि और उपयोग अधिकार केवल संगठित लाभार्थियों को। इस संगठित व्यवस्था में सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। ये संगठन पंचायत हो सकते हैं या गांव की सहकारी संस्था या ग्राम वन समिति हो सकती हैं।
- कार्यक्रम के तहत चुने जाने वाले क्षेत्र ऐसे किसी भी व्यक्ति के दावे से मुक्त होने चाहिए (मौजूदा अधिकारों, विशेषाधिकारों रियायतों समेत), जो योजना के तहत लाभार्थी न हो। किसी स्थल के लिए लाभार्थियों का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जिस किसी का भी चुने गए स्थल से होने वाली वनोपज पर किसी भी तरह का दावा हो, उसे संगठन में शामिल होने के अवसर से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
- कार्यकारी योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जानी चाहिए : वनों के संरक्षण, नए वन लगाने और वनों के प्रबंध में लाभार्थियों की भागीदारी।
- धन की व्यवस्था मुख्य तौर पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत वन विभाग द्वारा की जानी चाहिए। फिर भी ग्रामीण समुदाय को दूसरी एजेंसियों से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- वन भूमि पर खेती की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण समुदाय को ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी के पेड़ों के साथ–साथ आंवला, आम, महुआ आदि फलदार वृक्ष लगाने की भी अनुमति दी जा सकती है। इनके अलावा स्थानीय

तालिका – 1

राज्यों में 1 जनवरी, 2000 को सयुंक्त वन प्रबंध कार्यक्रम का विस्तार

क्रमांक	राज्य	सं.व.प्र. समितियों की संख्या	समितियों के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रति समिति औसत क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	6,706	16,79,084	250.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	5,810	446.9
3.	असम	101	3,060	30.3
4.	बिहार*	1,675	935,066	558.2
5.	छत्तीसगढ़	2,955	23,35,940	790.5
6.	गुजरात	1,150	133,461	116.1
7.	हरियाणा	351	60,477	173.1
8.	हिमाचल प्रदेश	203	62,000	305.4
9.	जम्मू और कश्मीर	1,599	79273	49.6
10.	कर्नाटक	1212	12800	10.1
11.	केरल	21	4000	190.5
12.	मध्य प्रदेश	9203	4125837	448.3
13.	महाराष्ट्र	502	94728	188.7
14.	मणिपुर	35	1400	40.0
15.	मिजोरम	129	12740	98.8
16.	नागालैंड	55	627	11.4
17.	उड़ीसा	3704	419306	113.2
18.	पंजाब	89	38991	438.1
19.	राजस्थान	2705	235634	87.1
20.	सिक्किम	98	2191	22.4
21.	तमिलनाडु	799	224389	280.8
22.	त्रिपुरा	160	23477	146.7
23.	उत्तर प्रदेश	498	44278	88.9
24.	पश्चिम बंगाल	3545	488095	137.7
25.	उत्तरांचल	7435	606608	81.6
	कुल	44943	11629539	261.4

* झारखंड शामिल है

स्रोत : आजीविका सुरक्षा तथा योजना आयोग, नई दिल्ली के निरंतर विकास के लिए भारत को हरा–भरा बनाने के बारे में कार्य बल की 2001 की रिपोर्ट

जरूरतों को पूरा करने, मृदा तथा जल संरक्षण में मददगार और अवक्रमित मिटटी/भूमि को उर्वर बनाने के सहायक झाड़ियां, फलियां और घास लगाने की अनुमति भी दी जा सकती है। लाभार्थियों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार देसी जड़ी–बूटियां भी उगाई जा सकती हैं।

- कार्यकारी योजना में निर्धारित व्यवस्था को छोड़कर ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित वन भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थियों का चयन केवल उन्हीं परिवारों में से किया जाएगा, जो भागीदार बनने के इच्छुक हैं और व्यक्तिगत प्रयासों के लिए तैयार हैं।

हालांकि देशभर में इस कार्यक्रम का स्वागत हुआ, फिर भी इस का अपेक्षित प्रभाव, मुख्य तौर पर निम्नलिखित सीमाओं में बंधा हुआ था :

- संयुक्त वन प्रबंध समितियों को संवैधानिक प्राधिकारों की कमी;
- केवल अवक्रमित वनों का ही कवरेज;
- विभिन्न गांवों के बीच और गांव के आपसी विवाद;
- देश भर में अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक मूल्य प्रणालियों का प्रचलन;
- जन–केंद्रित कार्यक्रम की बजाय लक्ष्य आधारित कार्यक्रम का होना;
- सुविधाप्रदाता आधारित कार्यक्रमों की बजाय, धन–बल आधारित कार्यक्रमों का होना;
- ग्रामीण समुदाय की अपेक्षित भागीदारी स्तर से काफी कम स्तर पर योगदान; और
- वन विभाग की नौकरशाही का उपेक्षापूर्ण रवैया।

वर्ष 1995 में, इस प्रस्ताव में मामूली फेर–बदल किया गया और इसमें महिलाओं तथा भूमिहीन परिवारों के साथ–साथ समुदायों द्वारा वन भूमि अधिकारों को भी शामिल किया गया। प्रस्ताव में 21 फरवरी, 2000 को और संशोधन किए गए तथा निम्नलिखित प्रावधान इसमें शामिल किए गए :

- **संयुक्त वन प्रबंध समुदायों को वैधानिक आधिकार** : सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत संयुक्त वन प्रबंध समितियों या ग्राम समितियों का पंजीकरण, गांव के सभी व्यस्कों को वन प्रबंध समितियों का सदस्य बनने का अधिकार।
- **संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी** : संयुक्त वन प्रबंध जनरल बाडी में कम से कम आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, जबकि संयुक्त वन प्रबंध कार्यकारी समिति/प्रबंध समिति में यह अनुपात कम से कम 33 प्रतिशत होना चाहिए। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव जैसा एक पद, समिति की किसी महिला सदस्य द्वारा भरा जाना चाहिए।
- **अच्छे वन क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंध प्रणाली विस्तार** : इस कार्यक्रम में अवक्रमित तथा अच्छे, दोनों ही तरह के वन आने चाहिए (सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को छोड़कर)। अवक्रमित वनों और अच्छे वनों के लिए (40 प्रतिशत से अधिक आच्छाद सघनता) माइक्रो योजना या उपचार योजना तथा सहमति–पत्र अलग–अलग होने चाहिए।
- **संयुक्त प्रबंध क्षेत्रों में माइक्रो योजना बनाना** : ब्योरेवार भागीदारी ग्रामीण आकलन के बाद यह योजना बनाई जानी चाहिए और इसमें स्थानीय समुदायों की खपत और आजीविका संबंधी जरूरतों के अलावा इन जरूरतों को निरंतर आधार पर पूरा करने के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए।
- **विवाद समाधान** : कार्यक्रम में शामिल विभिन्न भागीदारी समूहों में सदभाव बनाए रखने के लिए डिवीजन तथा राज्य स्तर के समूह गठित किए जाने चाहिए। इसमें गैर–सरकारी संगठनों सहित सभी संबद्ध पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **स्व–प्रेरित समूहों को मान्यता** : राज्यों में वन संरक्षण और वनारोपण के पुनर्वनारोपण के महत्वपूर्ण कार्यों में लगे सामुदायिक समूहों को पहचानना। उन्हें मान्यता देना और संयुक्त वन प्रबंध समितियों के रूप में उनका पंजीकरण करना जरूरी है। इसके लिए पहले उचित रिकार्ड रखने होंगे और जांच–पड़ताल करनी होगी।
- **संसाधनों के पुनर्निमाण के लिए योगदान** : संसाधनों को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जो अंतिम पैदावार से प्राप्त होने वाले राजस्व के एक खास अनुपात को वापिस निवेश कर सके। ग्राम समुदाय का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा अलग रखा जाना चाहिए और उतना ही अंशदान वन विभाग द्वारा बिक्री के अपने हिस्से से किया जाना चाहिए।
- **निगरानी और मूल्यांकन** : डिवीजन और राज्य स्तर पर प्रगति और प्रदर्शन के नियमित अंतरालों पर साथ–साथ निगरानी।

उम्मीद है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के तथा बाद के एक प्रमुख निगरानी योग्य लक्ष्य, यानी 2007 तक वन और वृक्ष आच्छाद में 27 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सयुंक्त प्रबंध कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

प्रगति

देशभर में इस कार्यक्रम को जबर्दस्त समर्थन मिला है। इसे व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है और इस पर अमल किया जा रहा है तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं

IAS/PCS

सफलता एक समग्र प्रयास का परिणाम ..... मणिकांत सिंह के अन्तर्गत 'The Study' नये कीर्तिमानों की ओर सदैव अग्रसर।

इतिहास
- मणिकांत सिंह

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

हिन्दी साहित्य
- कुमार सर्वेश

सामान्य अध्ययन
- मणिकांत सिंह
एवं विशेषज्ञों का एक समूह

संस्कृत साहित्य
- कैलाश बिहारी

कार्यक्रम

★ मुख्य परीक्षा

★ मुख्य परीक्षा
एवं
प्रारम्भिक परीक्षा
(समन्वित कार्यक्रम)

विशेष कार्यक्रम

★ संघीय लोक सेवा, मुख्य परीक्षा, 2004 में शामिल होनेवाले छात्रों के लिए इतिहास विषय में 120 घंटों का विशिष्ट कार्यक्रम। परन्तु इसके लिए एक टेस्ट परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।

★ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार लोक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विशिष्ट कक्षाएँ

THE STUDY
(An Institute for IAS)

210, IInd Floor, Virat Bhawan, (M.T.N.L. Bldg.) Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009, Ph. : 27653672, 27652263

की गई हैं। तालिका–1 में दर्शाए गए राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2001 तक 44,913 सयुंक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा 1.163 करोड़ हेक्टेयर वन का प्रबंध किया जा रहा था। प्रति समिति औसत प्रबंधित क्षेत्र 261.4 हेक्टेयर बैठता है।

तालिका से स्पष्ट है कि तीन राज्यों द्वारा मिलकर– मध्य प्रदेश (35.5 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (20.1 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (14.1 प्रतिशत) – सयुंक्त वन प्रबंध समितियों के तहत कुल मिलाकर 70.0 प्रतिशत वन क्षेत्र का प्रबंध किया जा रहा था। शेष 30 प्रतिशत वन क्षेत्र का प्रबंध, 22 राज्यों द्वारा किया जा रहा था। तालिका से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि राज्यों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र के औसत में भारी अंतर है। छत्तीसगढ़ में प्रति सयुंक्त वन प्रबंध समिति द्वारा प्रबंधित औसत क्षेत्र सबसे अधिक 790.5 हेक्टेयर था, जबकि कर्नाटक में यह औसत 10.1 हेक्टेयर मात्र था। दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी आपस में व्यापक अंतर है। उदाहरण के लिए, इन सात राज्यों में केवल अरुणाचल प्रदेश में प्रति समिति प्रबंधित क्षेत्र (449.9 हेक्टेयर) था, जो 261.4 हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था। फिर भी, शेष छह राज्यों में, यह औसत त्रिपुरा में 146.7 हेक्टयर, नागालैड़ में 11.4 हेक्टयर के बीच था।

रणनीति

रणनीति संसाधनों की क्षमता और क्षेत्र पर आधारित है। यह अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग हो सकती हैं। कुछ रणनीतिक कारवाईयां इस प्रकार है :

- अवक्रमित वनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यवहार्य जड़ों के स्टॉक का प्रयोग किया जा सकता है और पौधों को अंतर पर रोपा जा सकता है। आबादी वाले गांवों के आसपास के ऐसे सीमान्त वनों के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल किया जा सकता, जिनका छीजना अभी शुरू ही हुआ है और जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- अवक्रमित वनों को चरागाहों के जरिए पुनजीर्वित करना, जो वन काफी हद तक व्यवहार्य (छीज गए) हो गए हों और जिनमें स्टॉक न बचा हो, उन्हें नया जीवन दिया जा सकता है, जिससे वनाच्छाद किया जा सकता है।
- वनों में सागवान की उच्चकोटि की इमारती लकड़ी और इसके अन्य प्राकृतिक सहयोगी वृक्षों के जरिए वनों को फिर से लगाना।
- वनों की वृद्धि में मदद के लिए सागवान के सघन वनों में वृक्षों की वृद्धि और रोपण की गतिविधियां चलाना।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए बांस के प्राकृतिक वनों में पुनर्वनीकरण और नवीकरण
- सामुदायिक जमीनों, तालाबों के किनारों पर वनरोपण ताकि तालाबों के आसपास के गांवों की जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी और चारे की जरुरतों को पूरा किया जा सके।
- वनों और फलदार वृक्ष उगाने के लिए उन निजी भूमि पर वन रोपण, जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वृक्षों के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं है।

सुझाव

भागीदारी पर आधारित वानिकी के जरिए सयुंक्त वन प्रबंध कार्यक्रम में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने की जरूरत है। कुछ सुझाव निम्न प्रकार से हैं :

- आमतौर पर ग्रामीणों में और विशेष रूप से वानिकी प्रबंध में संभावित भागीदारों में वनों के संरक्षण, पुनर्वनीकरण और विकास में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने की सख्त जरूरत है।
- लोगों को सयुंक्त वन समितियों की बैठकों में अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेने के लिए राजी करना होगा। इसके लिए इन बैठकों को उत्सव का–सा रंग दिया जा सकता है। समिति की निर्धारित बैठकों के बारे में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। प्रचार के लिए, पोस्टरों, ढोल बजाने, घर–घर जाकर जानकारी देने आदि के तौर– तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्रामीण नौजवानों को समिति की निर्धारित बैठकों से कम से कम एक सप्ताह पहले समुदाय को वनों का भारी महत्व बताने वाले मंच, प्रदर्शनों/नाटकों/गीतों के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- वानिकी प्रबंध में भाग लेने वालों ग्रामीणों तथा वन पदाधिकारियों के बीच परस्पर सहयोग और समतामूलक कार्यक्रम कारगर अमल के लिए नितांत आवश्यक और अनिवार्य होता है।
- कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए इसका पारदर्शी होना बहुत ही जरूरी है। लाभार्थियों में लाभों के बंटवारे का मुददा पारदर्शी होना चाहिए। इस संबंध में राज्यों के विभिन्न प्रस्ताव बहुत ही अस्पष्ट है। आंध्र प्रदेश द्वारा अपनायी जाने वाली व्यवस्था को आदर्श माना जा सकता है।
- संयुक्त वन प्रबंध समिति और पंचायती राज संस्थानों के बीच संबंध कायम करने की तात्कालिक आवश्यकता है। इससे उनके आपसी विवाद निपटाने में सहायता मिलेगी और वानिकी प्रबंध के कार्यक्रमों को कारगर ढंग से समन्वित किया जा सकेगा।
- स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और संभावनाओं के तथा क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर माइक्रों योजना बनाई जानी चाहिए। वनरोपण स्थलों के चयन, प्रजातियों के चयन आदि में वानिकी विकास कार्यक्रमों को लागू करने में ग्राम पंचायतों को शामिल

किया जाना चाहिए।

- जनजातीय विकास ब्लॉकों में, ब्लॉक पंचायत और पंचायत, दोनों ही स्तरों पर, वानिकी विकास संबंधी एक कार्यकारी विषयनिष्ठ समिति अवश्य गठित की जानी चाहिए।

निगरानी और आकलन

किसी भी कार्यक्रम के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एक कारगर निगरानी तथा आकलन प्रणाली का होना जरूरी होता है। ऐसी प्रणाली बनाने के लिए कुछ मापदंड नीचे दिए जा रहे हैं :

- क्या वन विभाग और लोगों के परस्पर संबंध सुधरे है?
- कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी कितनी है?
- क्या ग्रामीण समुदाय को वनभूमि पर अवैध कब्जों से छुटकारा मिल गया है?
- वनोपज की तस्करी, किस हद तक रुक पाई है?
- वनों में आग लग जाने की स्थिति क्या है?
- वन भूमि पर चराई कितनी नियंत्रित हुई है?
- कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी का स्तर क्या है?
- क्या वनों पर निर्भर लोगों का पलायन स्तर घटा है?
- क्या वानिकी प्रबंध की पारदर्शी प्रणाली कायम हुई है?
- वन भूमियों के पुनर्जीवन और विकास में कितना सुधार हुआ है?
- दिहाड़ियों के रूप में, कितना अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ है?
- क्या लोगों को अतिरिक्त आमदनी का वास्तव में लाभ पहुंचा है?

संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध किए जाने वाले वनों की क्षमता को ठीक–ठीक पहचान कर उपयुक्त प्रबंध प्रणालियां तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए, अवक्रमित वनों की प्रबंध प्रणाली अच्छे वन प्रणाली से मिली होगी। लोगों की वन संवृद्धि तथा आजीविका संबंधी जरूरतों को अवक्रमित वनों के लिए व्यापक माइक्रो योजना में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ, समान क्षेत्र में वनों के प्रबंध में गैर इमारती वनोत्पादों के निरंतर इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली का एक अभिन्न घटक है। गैर इमारती वनोत्पादों के लिए बैकवर्ड और फारवर्ड संपर्कों की एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम पर कारगर ढंग से अमल करने से देहातों में ग्रामीणों के लिए लाभप्रद रोजगार उत्पन्न करने, गरीबी दूर करने, और परिणामस्वरूप आमदनी और रोजगार के उच्च स्तर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ❑

(डा. पी.के. सक्सेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। संप्रति योजना आयोग में)

When she looks to you for help in realising her fondest dream...

Give her THE POWER TO ACHIEVE

You have seen her grow from a screaming toddler to a sensitive teen-ager. Fragile one moment, fiercely independent the other. A dreamer seeking her life's mission. A young woman with a clear mind and a compassionate heart, nursing a desire to become a doctor of medicine. The young achiever in her pushes her to pursue her passion. The little girl in her looks to you for understanding and support. And you are willing to go the extra mile to help her achieve her goal.

Be assured that we at Brilliant will be with you. Which means that your daughter will be groomed and guided to her goal by a pioneer, whose correspondence courses have helped thousands of aspirants excel in competitive entrance exams – for more than 30 years.

Now, shouldn't you give your daughter the power of the pioneer?

MBBS
- **2-Yr. CBSE-PLUS** with Question Bank **(QB) + B.NET** (Brilliant's National Evaluation Tests) for MBBS Entrance 2006 (Std. XI)
- **1-Yr Course** with **QB + B.NET** for 2005 (Std. XII)
- **QB + B.NET** for 2005 (Std. XII)
- **TARGET-MBBS:** Primer Courses for students of Std. IX, X

MBA
- MBA Entrance Exams. 2005 starting with IIM-CAT 2004
- Target MBA: For early preparation towards 2006 Exams.

MCA
- MCA Entrance Exams. 2005

IIT-JEE
- **2-Yr. ELITE** Course with **YG-FILE + B.MAT** (Brilliant's Mock Admission Tests) for 2006 (Std. XI)
- **1-Yr. Course** with **YG-FILE + B.MAT** for 2005 (Std. XII)
- **YG-FILE + B.MAT** for 2005 (Std. XII)
- **TARGET-IIT:** Primer Courses for students of Std. IX, X

ENGINEERING
- **AIEEE** – 1-Yr. **Course** for **CBSE's All-India Engg. Entrance Exam.** 2005
- **SEAT** – 1-Yr. **Course** for State Engineering Admission Tests, 2005

GATE
- GATE 2005

IAS, ESE
- Civil Services Exam. 2005
- Engg. Services Exam. 2005

CSIR-UGC/ UGC(NET)
- JRF/L Exams. Dec. '04, June '05

AMIE
- Section A, B Exams. Dec. '04, June '05

GEOLOGISTS' Exam. 2004

GRE, TOEFL, BANK P.O.
- Year-round enrolment

BRILLIANT TUTORIALS®

For free prospectus and application form for the course of your choice write, call, fax or access our website: www.brilliant-tutorials.com

Box: 4996-YOH, 12, Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017,
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquires@brilliant-tutorials.com

IAS/PCS

सफलता का सरलतम मार्ग....

प्रशासनिक अध्ययन संस्थान
Institute of Administrative Studies

वर्तमान और भविष्य का सुरक्षित और अंकदायी विषय

लोक प्रशासन

द्वारा

अशोक कुमार दुबे

12 वर्षों से अधिक का सफल अध्यापन अनुभव

इतिहास विशेषज्ञों द्वारा

विश्व इतिहास तथा मानचित्रण पर विशेष बल

सामान्य अध्ययन

अशोक कु. दुबे, मो. के. बशर व विशेषज्ञ टीम द्वारा

(G.S. मॉड्यूलर में भी उपलब्ध)

मो0 के0 बशर द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था (G.S.) पर द्वितीय बैचः- 22 July

SC/ST/OBC/HC & महिलाओं को शुल्क में विशेष रियायत

सही दिशा + सही प्रयास = लक्ष्य प्राप्ति
हम + आप = लक्ष्य प्राप्ति

लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति

- सरल, सम्पूर्ण व गुणात्मक पाठ्यसामग्री
- मॉडल व दृश्य माध्यम द्वारा विषय का जीवंत अध्यापन
- प्रश्नोत्तर में सकारात्मकता एवं सृजनात्मकता का पर्याप्त उपयोग
- G.S. में उपेक्षित बिन्दुओं पर भी समान रुप से बल
- मौलिक प्रश्न-पत्रों के माध्यम से नियमित प्रगति जाँच

CLASSES START

Foundation Batch :- 10 Aug.

Mains Special Batch
(After one week of declaration of PT Result)

Admission Open

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

छात्र और छात्राओं के लिए पृथक आवास और भोजन सुविधा

102/B-14, Ist Floor, Com. Complex, Near HDFC ATM,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

Ph. 27651002, 31199055,
9811291166

वैज्ञानिक उद्यमियों के माध्यम से विश्वस्तरीय उत्कृष्टता

○ किरण मजूमदार शाह

बायोकॉन ग्रुप की मुख्य प्रबंध निदेशक पद्मश्री श्रीमती किरण मजूमदार शाह द्वारा 12 मई, 2004 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर अभिभाषण।

सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी आर्थिक ज्ञान की दो केन्द्रभूत शक्तियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तकनीक वैज्ञानिक खोजों के इतिहास में एक साथ हुई। भौतिक शास्त्री विलियम शॉक्ले ने सन 1951 में दुनिया के पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया जबकि जैवशास्त्री वॉटसन और क्रिक 1953 में डी एन ए के आविष्कर्ता बने। इस प्रकार इन दोनों ने जैव विज्ञान की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त किया। इसके थोड़े की दशक बाद ये आविष्कार आर्थिक ज्ञान के सशक्त उपयोग में काम आए। 1970 का दशक कम्प्यूटर युग का प्रारंभिक काल बना और 1980 के दशक ने डी एन ए तकनीक अथवा जेनेटिक अभियंत्रण के क्षेत्र में अपनी पहचान दर्ज कराई। 1990 का दशक पूर्णतः सॉफ़्टवेयर अथवा कम्प्यूटर साइंस के नाम समर्पित था। नई सहस्त्राब्दि जिनोमिक्स के जन्म की साक्षी रही। नई सहस्त्राब्दि ने इन दोनों केन्द्रभूत तकनीकों का इस अर्थ में मिलन कराया कि सूचना तकनीक जैव ज्ञान के क्षेत्र में जैव सूचना के मामले में जैव तकनीक के लाभप्रद उपयोग की खोज का स्रोत बना जबकि जैव तकनीक के सूचना तकनीक में उपयोग जैव– इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोचिप्स, बायोसेंसर्स और नेनो टेक्नोलॉजी के उद्भव का कारण बना।

इन तकनीकी क्षेत्रों में भारत की भागीदारी की जांच करना बहुत दिलचस्प है। एक ओर कम्प्यूटर युग ने लगभग भारत को दरकिनार कर दिया। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर क्रांति का भारत पर इतने विशाल ढंग से असर हुआ कि भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रशंसनीय रूप से अपनी पैनी दृष्टि से इस अवसर का इतनी तेजी से लाभ उठाया कि भारत विश्व में इस तकनीक के विकास का अगुआ बन गया।

जहां तक जैव प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, भारत की दिशा नीति–निर्धारण से कहीं ज्यादा अवसर को पहचानने की रही है। अनुसंधानकर्ता किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की बजाय आधुनिक जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से जूझते रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जिसमें वह बिना स्पष्ट दूरंदेशी की ओर ध्यान नहीं देकर खंडित–विखंडित ढंग से आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जिनोमिक्स के उपयोग से जूझता रहा। इतना तक कि जैव तकनीक के बारे में विश्व नीति अथवा कोई स्पष्ट अवधारणा तैयार करने के मामले में सरकार की नीति कोई खास महत्वपूर्ण नहीं रही।

जैव टेक्नोलॉजी क्षेत्र को वैसी सूचना प्रौद्योगिकी का अनुसरण करने और विश्वव्यापी वैशिष्टय सबल दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है जहां वह अपनी एक सशक्त भूमिका रेखांकित कर सके।

सबसे पहले हम इन दोनों क्षेत्रों के बीच अपने दृष्टिकोण की समानांतर रेखा खींचकर देखें। दोनों क्षेत्रों की तुलना से स्पष्ट है कि उनमें एक–दूसरे के प्रति बहुत सबल निर्भरता जैसी समानताएं हैं:

1. मानवीय पूंजी
2. कार्यगत पूंजी
3. सरकारी नीतियों में सहायता

फिर भी जब हम निम्न बिन्दुओं पर नजर डालें, तो दोनों में कुछ स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर होंगे:

- नियामक आवश्यकताएं
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार
- विकास की समय रेखाएं

ये अंतर जैव टेक्नोलॉजी के प्रति अलग–अलग रुख की अपेक्षा रखते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि भारत अपने मानवीय बौद्धिक पूंजी और कीमत के मामले में प्रतिस्पर्द्धा के कगार पर है। जैव–विविधता और प्रौद्योगिक क्षमताएं इसे प्रतिस्पर्द्धा के कगार के निकट ले जाती हैं। भारतीय जैव तकनीक ने अनुसंधान और निर्माण के क्षेत्र में अपनी क्षमताएं विश्व भर में रेखांकित कर दी हैं और तब जब इन क्षेत्रों में नवीनता के स्तर

उल्लेखनीय हैं। इस बात को उजागर करना महत्वपूर्ण है कि अब तक नवीनता, आविष्कारजनित होने की अपेक्षा ज्यादातर अनुकरणीय रहा है। इसी वजह से भारत का विश्व जैव–तकनीक पर प्रभाव अब तक सीमित रहा है। इसलिए भारत को अपनी खोजों को नवीनता की नीति से परिचालित करना होगा क्योंकि जैव तकनीक में विश्वस्तरीय नेतृत्व के स्वप्न को साकार करने के लिए सही मार्ग भारत के पास उपलब्ध है। इस प्रकार की मांग है कि राष्ट्रीय जैव तकनीक मिशन कम से कम लागत पर उच्च स्तरीय तकनीक के क्षेत्र में नवीनता के विकास पर ध्यान दें।

जैव प्रौद्योगिकी मिशन के साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकार को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ऐसी ढांचागत व्यवस्था तैयार हो सकेगी जो आई पी आर को सहयोग दे सके। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इच्छुक लोगों को आई पी आर व्यवस्था को अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि तभी वह विश्व में भारत को सर्वोच्च स्थान की पंक्ति में ला खड़ा कर सकेगा। इस दृष्टि से पहली जनवरी, 2005 का दिन भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा क्योंकि इसी समय एक नई मानसिकता, एक नए युग और सबसे बढ़कर एक नए सुअवसर की शुरुआत का सूर्योदय होगा।

यह हर्ष का विषय है कि पेटेंट करने की संस्कृति धीरे–धीरे सही, लेकिन एक सुन्दर भविष्य की दिशा में पांव बढ़ा रही है, फिर भी गति में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाने की जरुरत है। यह उत्साहजनक बात है कि पी सी टी चार्ट के मामले में भारत का बीसवां स्थान है और विकासशील देशों में तीव्रतम विकास दर के मामले सबसे अव्वल नंबर पर है। इसके लिए वास्तव में प्रो. मशेलकर बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सी ए आई आर के भीतर जो भारत में पी सी टी तालिका में अव्वल नंबर पर है, एक जबर्दस्त व्यवस्था को जन्म दिया। सन 2003 में पी ए आई आर के तीस प्रयोगशालाओं में पेटेंटीकरण के 124 मामले दर्ज कराए जा चुके थे। वैसे सांख्यिकी शास्त्रकारों के एक वर्ग में यह भी मान्यता है कि 2003 में भारत में पी सी टी के 611 पेटेंट दर्ज कराए जबकि कोरिया ने 2,947। अलग–अलग ही सही लेकिन इनमें एल जी और सैम्संग का अकेला योगदान पांच सौ पैंसठ पेटेटों का था।

यह सही है कि नित नए विचार के अभाव में तब तक कोई खोजपूर्ण कार्य संभव नहीं है जब तक कि इस उद्योग के भीतर वैज्ञानिकों, विज्ञानशालाओं और अनुसंधानवेत्ताओं के बीच एक सशक्त और गत्यात्मक संबंध नहीं हो। लेकिन यह तथ्य भारतीय उद्योग के लिए अभी दूर की बात है और जब तक नीतिगत रूप से इन दोनों में ताल–मेल नहीं होता, विश्व में भारत अपना प्रभाव दर्ज नहीं

RAO IAS
THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS
14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोनः 2601624
हिन्दी माध्यम पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध
नक्कालों से सावधान
WE HAVE NO BRANCH AT DEHRADOON
IAS/PCS (Pre & Main) बैच 13 जुलाई से प्रारम्भ
भूगोल विजय कुमार मिश्र
वैकल्पिक विषय (Pre & Main) द्वारा
• नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी • 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
• प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण • सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
• पांच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण • अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट
• सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश • नवीनतम आँकड़ों से सुसज्जित अध्ययन सामग्री
विषय उपलब्ध :- सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र,
विवरण पुस्तिका हेतु रू० 50/- M.O. से भेजें
SATYA

कर सकेगा। समीर ब्रह्माचारी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटेग्रेटिव बायोलॉजी एंड निकोलस पीरामल ने इस दिशा में कारगर पहल की है जिसका अनुसरण आदर्श योग्य है।

बात 1978 की है। लॉस एंजेल्स के नजदीक एक अनुसंधान संस्थान सिटी ऑफ होप नेशनल मेडिकल सेंटर को जेनेटेक इनकों के लिए मानव इंसूलिन के वास्ते एक क्रांतिकारी डी एन ए तकनीक तैयार करने का लाइसेंस मिला। इस संस्थान को आश्चर्यजनक रूप से दो सौ सत्तर मिलियन डालर सिर्फ रॉयल्टी के रूप में मिले। संस्थान की तरक्की का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा और इसे मानव हारमोन विकास, इंटरफेरोन, हेपाटाइसिस – बी और दूसरे औषधीय उत्पादनों के लिए रायल्टी की मात्रा में बढ़ोत्तरी होती रही। इस संस्थान ने लाइसेंस का उपयोग जी एस के, शीरिंग प्लाऊ और अन्य कम्पनियों के साथ मिल–जुलकर किया। यह अनुसंधान का एक पहलू है। जेनेटेक को इस भागीदारी से बेहिसाब मुनाफा हुआ और देखते ही देखते वह विश्व का अग्रणी जैव तकनीकी कंपनी बन गया।

नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और नेशनल साइंस फांउडेशन ने कई ऐसी दवाइयां तैयार की है। नामी–गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के माध्यम से ये दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं लेकिन इसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण विभिन्न सरकारी समायोजित अनुदान और अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं जो उद्योग और शैक्षणिक अनुसंधान की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद पहुंचाती है। इन संस्थाओं विश्वविद्यालयों के साथ मिल–जुलकर कई जैव औषधियों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। आश्चर्य की ही बात है कि अमेरिका की अस्सी प्रतिशत बायोटेक कंपनियों के विकास, उद्भव और सफलता के पीछे मुख्यतः विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों का सक्रिय योगदान है।

1988 में यू एस एफ डी ए ने नेशनल इंस्टीट्यूट से लाइसेंसशुदा छह दवाइयां स्वीकृत कीं। ये दवाइयां मेडिक्यून, वाचेय, जेनजाइम आदि थीं जो वार्षिक स्वीकृत दवाइयों का पांच प्रतिशत है। लेकिन 2003 में यू एस एफ डी ए द्वारा स्वीकृत दवाइयों का सत्तर प्रतिशत लाइसेंस शैक्षणिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत को अपने वित्तीय साधनों और प्रतिदर्श के माध्यम से उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच ऐसे मजबूत संबंध बनाने के कार्य को उत्साहित करना होगा।

यदि भारतीय बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की जांच करें तो पता चलेगा कि उद्यमी वैज्ञानिकों ने अवेस्थाजेन, बेंगलौर जीनी, भारत बायोटेक, बायोकॉन, गंगाजेन, मेटालेलिक्स, शान्ता बायोटेक, स्ट्रैंड जिनोमिक्स और एक्स–साइटन जैसी अनेक अग्रणी कंपनियों की स्थापना की है। इनमें से कुछ को छोड़कर अधिकतर

Aspiring for M.E. or M.Tech from a prestigious institution?

BRILLIANT'S POSTAL COURSES FOR

GATE 2005

SUBJECTS OFFERED • Computer Science & Engg. • Information Technology • Electronics & Comm. Engg. • Electrical Engg. • Instrumentation Engg. • Mechanical Engg. • Production and Industrial Engg. • Civil Engg. • Geology & Geophysics • Mathematics • Physics • Chemistry • Engg. Sc. (Engg. Maths, Electrical Sc., Materials Sc., Solid Mechanics, Fluid Mechanics, Thermodynamics) • Life Sc. (Chem., Biochem., Microbiology)

Two of Brilliant's students have secured the No.1 rank in GATE 2004. (Information about top ranks still being received)

With 2 No. 1 ranks, With 70 ranks above the 99th Percentile and 471 ranks above the 90th Percentile, a whopping 674 of our students were successful in GATE 2003.

Aspiring for
Junior Research Fellowship?
Want to be a
University / College Lecturer?

Be guided by Brilliant Tutorials.

CSIR-UGC NET
JRF/L EXAM
Dec '04 & June '05

UGC NET
JRF/L EXAM
Dec '04 & June '05

SUBJECTS OFFERED
• Chemical Sciences
• Mathematical Sciences
• Physical Sciences
• Life Sciences
The course is a comprehensive, extensively researched package covering your subject of specialisation. 8 sets of study material cover the syllabus thoroughly while a Doubt Letter Scheme allows you to clarify doubts with our professors.

SUBJECTS OFFERED
• Economics • Commerce
• History • English
The course covers all the requirements of Papers I, II, III(A) and III(B) of the subject of your specialisation.
8 sets of study material cover the syllabus thoroughly while a Doubt Letter Scheme allows you to clarify doubts with our professors.

AIEEE 2005

Your gateway to the National Institutes of Technology

All the Regional Engineering Colleges have been upgraded to National Institutes of Technology and accorded the status of Deemed Universities. And, admission to all of them, as well as to many other institutions of specialized engineering education, will be on the basis of the AIEEE [All India Engineering Entrance Examination].
Now, who can equip you for success in this highly competitive exam, better than Brilliant Tutorials – a 30-year veteran who has helped produce thousands of winners and hundreds of top-rankers in competitive entrance exams all over India.

Course Highlights:

• 8 sets of lesson material and assignments • 3 Postal Tests in each subject • A ready-reference compendium of important formulae, equations and data in Maths, Physics and Chemistry • 4 National Sit-down Tests at 26 centres across the country • 4 Home-based Mock Test Papers • Doubt Letter Scheme

Admission open, Write, call or fax for free prospectus.

BRILLIANT TUTORIALS®

Box: 4996-YOE 12, Masilamani Street, T. Nagar, Chennai-600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829
e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

ADMISSION ALSO OPEN FOR THE FOLLOWING POSTAL COURSES FROM BRILLIANT
• IIT-JEE 2005, 2006 & beyond • MBBS Ent. 2005, 2006 & beyond • MBA Ent. 2005 • MCA Ent. 2005 • IAS 2005 • ESE 2005 • AMIE Section A, B Exams. Dec. 2004, June 2005 • GRE • TOEFL • BANKING • GEOLOGISTS' Exam. 2004

वैज्ञानिक निजी क्षेत्र के अनुसंधान प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध हैं। शैक्षणिक संस्थाओं से इनका प्रायः कोई सरोकार नहीं रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम एक कारगर कार्यक्रम बनाएं जिसमें हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उद्यमी वैज्ञानिक तैयार किए जा सकें जो उद्योग और शिक्षणशालाओं के बीच अत्यावश्यक संबंधों को तेजी से जांच–परख करके अनुकूल वातावरण तैयार करने में सक्षम हो सकें।

आज स्थिति यह है कि अधिकतर भारतीय वैज्ञानिक अपने भीतर दबे–सिकुड़े और सीमित उत्साह को लेकर व्यावसायिक लाभ के लिए एकाकीपन में काम करते हैं। अब समय आ गया है कि भारत प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं तैयार करे जिससे हमारे वैज्ञानिक बौद्धिक संपदा के विकास के लिए उत्साह का अनुभव करें। साथ ही वैज्ञानिकों को अपनी बौद्धिक सम्पदा की बिक्री तथा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पूरा अवसर मिल सके।

आखिरकार टेक्नोलॉजी एक व्यावहारिक वैज्ञानिक ज्ञान है और हमारे उद्यमी वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक ज्ञान को तकनीकी धरातल पर साकार रूप देने में सबसे ज्यादा सक्षम हो सकते हैं।

मैं सरकार द्वारा शुरू किए गए निमिटली (NIMITLI) कार्यक्रम की खासतौर से सराहना करना चाहूंगी क्योंकि इस कार्यक्रम ने हमारे राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी नीति को पालनकर्ता का स्वरूप दिया है। इस कार्यक्रम ने अनेक औद्योगिक शैक्षणिक अनुसंधान भागीदारी को बढ़ावा दिया है और मुझे विश्वास है कि यह हमारे वैज्ञानिकों की उद्यमशील आकांक्षाओं को उचित प्रोत्साहन देकर एक सही ढांचागत आधार तैयार करने में सहायक होगा। मैं इस दिशा में डीबीटी, टीडीबी और अन्य राज्य सरकारों द्वारा की गयी पहल की भी चर्चा करना चाहूंगी जिन्होंने बायोटेक कंपनियों की धन सम्बंधी जरूरतें पूरी करने में सहयोग किया है। यह अलग बात है कि इस उद्योग के सारे पहलुओं के सम्पूर्ण विकास के लिए अधिकाधिक धनराशि और आवश्यक रचनात्मक समाधान उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अनुसंधान कार्यों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को आवश्यक धनराशि मुहैय्या कराने के साथ–साथ विकास और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग के भीतर धनराशि में बढ़ोत्तरी आवश्यक है। यही समग्र दृष्टिकोण इसकी सफलता की कुंजी है।

अंत में मैं बौद्धिक सम्पदा के विकास, उद्योग शिक्षणशाला अनुसंधान संबंध और वैज्ञानिक समुदाय में उद्यमिता के मानस के विकास के महत्व पर जोर देते हुए जिस अहम बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, वह है सरकार की उन व्यावहारिक सैद्धांतिक नीतियों पर अमल करना जो भारत को विश्व में बायोटेक के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सकें। ❑

OUR MILESTONES

"I found guidance from *Dr. Majid Husain* at CIVILS INDIA very useful one. CIVILS INDIA provides good environment for studying Optionals and General Studies."
Arshdeep Singh

ARSHDEEP SINGH
IAS 3rd Topper

"With labour and commitment Proper guidance matters the most which I got at CIVILS INDIA"
Shurbir

SHURBIR SINGH
IAS 4th Topper

OTHER RESULTS

138th - Dinesh Kumar
145th - Dheeraj Garg
252nd - Shyam Kanu Mohanta
318th - Punam
402nd - Babulal Sonal

OUR HIGHEST IN 2003
Geog.-362; G.S.-361; Essay-142; Interview-220

IAS 2004-05
ADMISSION NOTICE
We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

GEOGRAPHY
by Prof. Majid Husain
"A name needing no introduction"
*6th Toppers in the very first Batch (2002) and 3rd & 4th Topper in the second Batch (2003)

GEN. STUDIES, PUB. AD, SOCIO., ECONOMY & ESSAY
by Dr. Ramesh Singh
"Students say him ultimate guide"
4th Topper in the very first Batch (1998)
6th Topper in (2002) & 3rd and 4th in 2003.

PERSONAL GUIDANCE PROGRAMME (PGP)
In G.S., Pub. Ad., Socio., Essay, History Useful for those who (Eng. & हिन्दी) :-
1. Written Mains but could not score better.
2. Have taken coaching but not fetching good marks.
3. Can't join regular classes due to any reason.

*Half fee of the classroom course.

ADMISSION OPEN
HISTORY by Sanjay Varma
हिन्दी साहित्य by Sarvesh Pandey & Tryambak Nath

CIVILS INDIA
An Institute For IAS

A/12-13, 202-203, ANSAL BUILDING, BEHIND BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Ph.: 27652921, 27651344, 9810553368, 9818244224

PUBLIC ADMINISTRATION

Topics Which Deserve Your Special ATTENTION FOR MAINS

⏭ First Generation of reforms in Pb. Adm.(Global Perspective)	:	Efficient but insufficient (A critical evaluation)
⏭ New Public Management	:	An Neo Concept heading towards untimely demise.
⏭ Corporate Governance	:	What lies in the beneath? mere a buzz word with less significance.
⏭ Civil Society	:	Its significance for failed states and banana republics. (Strength, Weakness & possibilities)
⏭ Market Vs state Debate	:	Much ado about nothing.
⏭ Theory of Roll back of state	:	Is really state Rolling back. (What Global trends suggests)
⏭ Good Governance	:	An Normative concept with little appliedness.
⏭ Right-To-Information	:	Expectation, limitation & Relevance for Democratic Societies.
⏭ Citizen's Charter	:	A mere window dressing exercise which utilises a very limited and inappropriate concept of citizenship.
⏭ Corporate Social Responsibility	:	How is it redefining public Vs Private debate.
⏭ Development Administration	:	How effective is contemporary approach (Decentralize governance)
⏭ Problem of digital divide	:	In the context of Administrative Reform and e-governance.
⏭ Judicial Consumerism in India Administration.	:	How to ensure effective Judicial control over
⏭ A Transparent Financial Information System	:	An prerequisite for a sound government budgetary control.
⏭ Indian Socialism	:	Is it facing unnatural death? Its relevance in era of LPG
⏭ Position of Prime Minister	:	Mere a Bimbpurusha not a Pratyakshapurusha (in the era of coalition politics)
⏭ Cabinet Secretary	:	Senior most civil servant of the land or senior most pen pusher of the land? (in the context of the PMO)
⏭ Indian Planning	:	In search of Relevance.
⏭ Fiscal Federalism in Market Era	:	How to create a proper balance.
⏭ Profit Making PSU's	:	Strategic management OR Disinvestment? (What is proper way?
⏭ All India Services	:	Last out post of the Empire or sine qua non of governance (its relevance in 21st century)
⏭ Indian Police Service	:	Strength, weakness, opportunities and threat (in the context of rapid privatization of policing)
⏭ Indian Economic Reform	:	How these reforms are redrawing India's social landscape (Winner elite class, emerging middle class, & loser lower class)
⏭ CAG Institution	:	How to make it accountable, responsible, less bureaucratic and more result oriented.
⏭ De-Collectrization Process in District Administration	:	Emerging rural Democracy & Problem of proper relationship.

By S.N. UNIYAL | IN ENGLISH तथा हिन्दी माध्यम | Mains Batch 14 July 2004

GALAXY 2703, Dr, Mukherjee Nagar Bandh, Adjoining Laxmi Boy's Hostel, Delhi-110009, 9818906330

भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण नीति 2004–2005

○ जी. श्रीनिवासन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रा और ऋण नीति से संबंधित अपना वार्षिक विवरण जारी कर दिया है। विवरण में सन् 2003–04 के दौरान अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र से प्राप्त लाभ को संचित बनाए रखने की ओर स्पष्ट रूप से सतर्क किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से परिवर्तित ठोस सूक्ष्म अर्थगत बुनियादों के अनुरूप देश के अग्रणी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2004–05 के लिए अपनी मौद्रिक और ऋण–नीति 18 मई, 2004 को मुम्बई में जारी कर दी। मौद्रिक नीति में कुल मिलाकर ऋण संबंधी बढ़ोत्तरी, पूंजी निवेश में मज़बूती तथा निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिवर्तनीयता का प्रावधान है। इसके साथ ही मूल्य स्तर की गति पर भी पैनी निगाह रखने की व्यवस्था है।

इन उद्देश्यों के अनुरूप ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक दर छह प्रतिशत पर स्थिर रखी है जबकि रिपो (पुनर्वित्त) दर बिना किसी परिवर्तन के साढ़े चार प्रतिशत है। बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वे ऋण के लेन–देन और ऋण–संबंधी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उससे जुड़े जोखिम के मूल्यांकन को ऋण के मूल्य के साथ जोड़ें। व्यास समिति की अंतरिम रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को मानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावों के समूह को लागू करने का निर्णय किया है। इसमें प्राथमिकता क्षेत्र में आने वाली संग्राहक सुविधाओं के लिए कर्ज़, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के समान ही कृषि ऋण, एक सीमा तक खास तरह के कृषि ऋण के लिए संरक्षित आवश्यकताओं को उठा लेने और एक फ़सल से दूसरी फसल के मौसमों के लिए गैर कार्यशील खातों को एक–दूसरे के साथ जोड़ने की बातें शामिल हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी नीति और नियमों में जो परिवर्तन किए हैं, उनसे बैंकों को सार्वजनिक अथवा निजी, दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं की बुनियादी संरचना के लिए ज्यादा धन मुहैय्या करने में सफलता मिलेगी। अब तक स्थिति यह थी कि बैंकों की बुनियादी संरचना के लिए व्यक्ति अथवा व्यक्ति–समूह जैसे कर्जदारों को पूंजीगत धन का क्रमशः पंद्रह और चालीस प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति थी। इसमें पहले मामले में अतिरिक्त दस प्रतिशत बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए ऋण देने की सुविधा थी। कुछ बैंक इन निर्धारित सीमाओं से ज्यादा ऋण स्वीकृत करते हुए शीर्षस्थ बैंक से उनके अनुमोदन का आग्रह करते रहे हैं। कई मामलों में आग्रह मान भी लिए गए हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण संबंधी धन की वास्तविक जरूरत की जानकारी नहीं मिली और उसे अंततः बैंक और कर्ज़दार की बातों पर विश्वास करने को विवश होना पड़ा। इस अनावश्यक विसंगति को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पूंजीगत धन की अधिकतम और पांच प्रतिशत राशि मुहैय्या कराने की स्वीकृति दे दी है बशर्ते कर्ज़दार बैंकों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का उपयुक्त खुलासा करने को सहमत हों। इसके फलस्वरूप किसी व्यक्तिगत कर्ज़दार को पच्चीस प्रतिशत और समूह के पचपन प्रतिशत तक कर्ज़ मिल सकेगा। यह सीमा उस स्थिति में आड़े नहीं आएगी जब बैंक की राशि की पूरी गांरटी भारत सरकार ने ले रखी हो। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि बैंकों के लिए कर्ज़ देने की अब कोई सीमा नहीं है और वे एन. टी.पी.वी. जैसे सरकारी गांरटी वाली सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को कर्ज़ दे सकते हैं, हालांकि इसका अर्थ ऐसा नहीं कि नीतियों अथवा नियमों के साथ इनका ताल–मेल किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी ने इस महत्वपूर्ण नीति की चर्चा करते हुए बताया कि बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बहुत ज्यादा धनराशि की जरूरत है जबकि पूंजीगत बाज़ार इस दिशा में विकसित नहीं हैं। सरकार ने भी पूंजी लगाना बंद कर दिया है और कर्ज़ देने की बैंकों की

सीमा से उन्हें भारी परेशानी हो रही थी। किसी व्यक्ति अथवा समूह को कर्ज देने की अधिकतम सीमा में पांच प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। डॉ. रेड्डी ने यह स्पष्ट करने में जरा भी देरी नहीं की कि परियोजना के लिए विशिष्ट गारंटी अवश्य होनी चाहिए ताकि बैंकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए जारी धनराशि के प्रवाह की क्षेत्र–विशेष की परियोजना के साथ जुड़े जोखिम का असर जमाकर्त्ताओं की धनराशि पर नहीं पड़े।

इस नीति में कारपोरेट क्षेत्र की ऋण पुनर्व्यवस्था की ही तरह मझोले उद्योगों के ऋण की फिर से संरचना करने की व्यवस्था विकसित करने की बात शामिल है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय पुनर्व्यवस्था के लिए कर्ज की रकम बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाओं के लिए कर्ज़ की परिभाषा को और व्यापक बनाते हुए कार्य–दल गठित करने की बात की गई है। कर्ज़ प्राप्त करने योग्य निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना भी तैयार की गई है। बैंकिंग व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के आम उपयोग के लिए इस नीति में इसका ख़ास प्रस्ताव किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस को सेवा–शुल्क से मुक्त रखा जाए। पूंजीगत बाज़ार के लिए इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर पर एक कार्य–दल के साथ–साथ भुगतान और निपटान–व्यवस्था (पेमेंट एंड सेट्लमेंट सिस्टम) परिषद् के गठन की भी घोषणा की गई है।

भारतीय उद्योग के वैश्वीकरण के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में भारतीय कारपोरेट जगत् की साझेदारी वाली कम्पनियों को अपनी कुल धन क्षमता का शत–प्रतिशत भाग विदेशों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। वास्तविक क्षेत्र में निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा पहले ही पांच सौ डॉलर तक बढ़ा दी गई है और इसी तरह प्रवासी भारतीयों को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान पच्चीस हज़ार डॉलर तक की राशि मुक्त रूप से स्वदेश भेजने की छूट मिल गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदिग्ध सम्पत्ति के लिए गैर–कार्यशील सम्पत्ति की समयावधि के अनुरूप 31 मार्च, 2005 से तीन साल से भी ज्यादा समय तक के लिए बढ़ा दने की व्यवस्था कर दी है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार बैंकों को गैर–कार्यशील सम्पत्ति के बारे में उनकी समयावधि को ध्यान में रखते हुए स्तरीयता के आधार पर व्यवस्था करनी होती थी। लेकिन संदिग्ध सम्पत्ति के मामले में जो तीन साल से अधिक समय से हैं, उस सम्पत्ति के पचास प्रतिशत भाग के लिए पूर्ववत् व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि उसे गुम सम्पत्ति नहीं मान लिया जाता। बैंकों की बैलेंस शीट में सम्पत्तियों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है– स्तरीय, निम्न स्तरीय, संदिग्ध और गुम सम्पत्ति। लेकिन यह वर्गीकरण कर्ज़दाता के पुनः भुगतान के ढंग पर निर्भर करता है।

इसके साथ–साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। कि वे किस हालत में किसी सम्पत्ति के वास्तविक हक़दार को गलत या सही ठहरा सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने सुझाव दिया है कि वे किसी कर्जदाता को जान–बूझकर गलती करने का अपराधी मानने से पहले उसकी बात सुनने का उसे अवश्य अवसर दें।

बैंक की घोषित नीति में शहरी सहकारी बैकिंग व्यवस्था क्षेत्र को भी ठोस रूप से विकसित करने के उपाय करने की बात कही गई है। शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़, स्वस्थ और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि इस प्रकार के बैंकों के लिए व्यापक नीति तैयार होने के बाद ही कोई नया लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में इस क्षेत्र के बैंकों के लिए समुचित वैधानिक और नियामक व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे बैंकों की वित्तीय स्थिति मज़बूत बनाने के लिए यथाशीघ्र एक नीतिगत फार्मूला तैयार किया जाए।

आशा की किरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मूल्यांकन में वर्ष 2003–04 की घटनाओं और 2004–05 के प्रति अपने दृष्टिकोण में भरपूर आशावादिता जताई है। सर्वप्रथम, भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व के शीर्ष देशों की पंक्ति में शामिल हो सकता हैं। चालू वित्त वर्ष में इसका सकल घरेलू उत्पाद साढ़े छह से सात प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। दूसरी बात, नीति–संबंधी प्रयोजनों के लिए मुद्रा स्फीति की दर पांच प्रतिशत तक अनुमानित है।

बैंक ने इस बात का खास तौर से उल्लेख किया है कि लगातार प्रयासों के कारण ही मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में विश्वास की भावना पैदा हुई है, वैसे यह अलग बात है कि मुद्रा स्फीति–संबंधी आशाएं उल्टी भी पड़ सकती हैं अगर अपेक्षाकृत कम समय में मूल्यों में विपरीत उलट–फेर हो जाए। इसलिए बैंक ने चेतावनी भी दी है कि हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था के पास अच्छे संसाधन हैं और उनमें आपूर्ति के सदमे को उलट देने की क्षमता मौजूद है, फिर भी परिवर्तनीयता की सतत प्रचुरता पर सावधानीपूर्वक नज़र रखने की आवश्यकता है।

तीसरी बात, कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों और बुनियादी सुविधाओं के लिए कर्ज़ का भुगतान निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चौथे, हमारे वित्तीय क्षेत्र अपनी बढ़ती ताक़त, क्षमता और स्थिरता दर्शाते हैं। और, अंततः सार्वजनिक नीतियों के आचार के प्रति बाह्य क्षेत्रों की वर्तमान

वार्षिक मुद्रा नीति विवरण के मुख्य बिन्दु (2004)

- सकल घरेलू उत्पाद 6.5 – 7.0 प्रतिशत
- आपूर्ति का कोई खास सदमा नहीं पहुंचे और परिवर्तनीयता का समुचित प्रबंधन हो, वैसी स्थिति में मुद्रा स्फीति की दर प्रतिशत नीतिगत प्रयोजनों से 5 प्रतिशत
- सन् 2003–04 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 37.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि जो 7 मई, 2004 तक कुल 118.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
- भारत से निर्यात 17.1 प्रतिशत बढ़ा जबकि आयात 25.3 प्रतिशत। 2003–04 में लगातार तीसरे वर्ष चालू खाते में और इजाफा।
- 2003–04 के दौरान क्षेत्र का सर्वाधिक दिलचस्प पहलू अत्यधिक मात्रा में पूंजी का स्वदेश–प्रवाह।

समग्र मूल्यांकन

- कर्ज पाने योग्य निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना तैयार।
- तेल के मूल्य की समस्या और घरेलू परिवर्तनीयता के बावजूद सूक्ष्म स्थिरता की स्थिति पर किसी खास प्रभाव की कोई संभावना नहीं।
- कृषि तथा छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए बैंक–ऋण के आड़े आने वाली कठिनाइयाँ दूर करने पर जोर।
- ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन पर जोर ताकि देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में बैंक सेवा की गुणवत्ता, उद्देश्यपरकता और उनकी पहुंच सुनिश्चित हो।

मुद्रा नीति की विशेषताएं

- नीति तैयार करते समय अन्तर्राष्ट्रीय तेल अर्थ तंत्र पर भू–राजनीतिक जोखम के असर समेत अन्य अनिश्चितताओं पर ध्यान रखा गया है। इसलिए मुद्रा स्फीति की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाए और इसमें किसी तरह की कोताही के लिए गुंजाइश न हो।
- 2004–05 के लिए मुद्रा नीति के निर्देश कुल मिलाकर इस प्रकार होंगे (i) मूल्य स्तर के व्यवहार पर ध्यान रखते हुए कर्ज की बढ़ती मांग, निवेश सहायता और निर्यात की मांग पूरी करने के लिए परिवर्तनीयता की समुचित व्यवस्था (ii) उपर्युक्त के अनुरूप यथास्थितिवाद बनाए रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज–दर के ऐसे वातावरण का अनुसरण जो विकास की गति, और सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्था तथा मूल्य–स्थिरता जारी रख सके।

उपाय

- बैंक–दर 6.00 प्रतिशत पर स्थिर
- रेपो रेट 4.5 प्रतिशत पर यथावत्
- भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ विभाग में सभी प्रकार के लेन–देन के लिए एक ही स्थान पर सारी व्यवस्था
- जून, 2004 तक ऑन–लाईन कर लेखा प्रणाली चालू

स्थिति और दृष्टिकोण दुखद हैं। मूल्यांकन में स्पष्ट किया गया है कि विदेशी मुद्रा का भंडार 7 मई, 2004 तक 118.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया जब कि मार्च, 2004 के अंत तक कुल राशि 113 बिलियन डॉलर तक ही सीमित थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार संतोषजनक रहा है और यह विकास दर, अर्थव्यवस्था में बाह्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी और जोखिम समायोजित पूंजीगत प्रवाह के आकार के अनुरूप है। पहले की तरह विनियम दर प्रबंधन बिना निर्धारित अथवा पूर्व घोषित लक्ष्य के लचीलेपन पर आधारित रहा। इतना जरूर है कि इस व्यवस्था में हस्तक्षेप की गुंजाइश रखी गई।

मौद्रिक विकास की चर्चा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गर्वनर ने कहा कि 2003–04 में मुद्रा की सप्लाई में 16.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि उससे पहले के वर्ष में यह 12.8 प्रतिशत थी। इसी प्रकार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशि बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गई जबकि 2002–03 के दौरान यह राशि 13.4 प्रतिशत थी। आवासीय और खुदरा क्षेत्रों के नेतृत्व में गैर खाद्य ऋण बढ़कर 17.6 प्रतिशत हो गया। ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2004 के अंत तक गैर–खाद्य बैंक ऋण 20.5 प्रतिशत तक पहुंच गया जबकि 2002–03 में यह मात्र 16.4 प्रतिशत था।

सन् 2004–05 का केन्द्रीय बजट अभी संसद में पेश होना है, भारतीय रिजर्व बैंक की चालू वर्ष के लिए मुद्रा और ऋण नीति के बारे में जारी वार्षिक विवरण सन् 2003–04 के दौरान अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों में प्राप्त लाभों को संचित करने का एक प्रयास है। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के 2004–05 के वार्षिक नीति विवरण और केन्द्र में नई सरकार के गठन का समय–संयोग एक समान है, इस बात की सहज ही आशा की जा सकती है कि नई सरकार अर्थव्यवस्था के विवरणों की पूरी बारीकी से जांच–पड़ताल करेगी। इससे देश के शीर्षस्थ बैंक को अक्तूबर–नवम्बर, 2004 के अपने वार्षिक नीति विवरण की समीक्षा करने में मदद मिलेगी क्योंकि इस शीर्षस्थ बैंक के लिए ऐसा करना एक आम प्रथा है जिसमें आवश्यकतानुसार बीच में संशोधन किए जा सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था का चक्र अबाध गति से घूमता रहे। ❑

(श्री जी. श्रीनिवासन दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

A. TIWARI'S निष्ठा

सिविल सेवाओं की तैयारी हेतु एक उत्कृष्ट संस्थान

UPPCS 2001 – सफल अभ्यर्थी

UPSC, 2003 में 119 वीं रैंक

Ashish Kr. Singh - 061999

Anoop Singh 170132

Archana Upadhyay 09393

Akhilesh Kr. Shukla 146711

Manoj Kr. Pandey 92159

Manish Kr. Mishra 026439

Atul Kumar Singh 196493

Vagish Kr. Shukla 138609

Rakesh Kr. Kushwaha 176783

Pradeep Kr. Tiwari 168561

Sanjeev Kr. Singh 351656

Anjali Devi 142332

Ramesh Kr. Singh 122224

Dharmendra Kumar 125335

Ramendra Ratnakar 101664

Roli Nigam 065165

Yagesh Singh 179490

साक्षात्कार बैच के सफल अभ्यर्थी

Nistha Tiwari 210540

Vinay Kumar Pandey 48310

Guru Prasad Tiwari 114036

Mahendra P. Singh 189358

Binay Kumar Pandey 110694

Vipin Kumar Yadav 121974

Satya Prakash Verma 173686

Ravindra Nath Tripathi 001445

Geetanjali Singh 069016

Anamika Singh 045532

Sudesh Kumar Rai 060368

मेरी सफलता में निष्ठा कोचिंग के निदेशक अविनाश तिवारी का बहुत बड़ा योगदान है।

मनोज पाण्डेय

Dy. S.P. के पद पर चयनित

(हिन्दुस्तान में 6 Dec. को दिया गया साक्षात्कार)

दर्शनशास्त्र
(प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा)
अविनाश तिवारी, प्रो० द्विवेदी एवं अन्य, इलाहाबाद

हिन्दी साहित्य
डॉ० विनोद कुमार मंगलम - पटना

समाजशास्त्र
सुप्रसिद्ध अध्यापक द्वारा - इलाहाबाद

इतिहास
प्रो० लाल बहादुर वर्मा, प्रो० आईबी.झा,

सामान्य अध्ययन
सी.बी.पी. श्रीवास्तव, डिस्कवरी, दिल्ली

भूगोल
गोपाल तिवारी, दिल्ली

लोक प्रशासन
राजेश सिंह, दिल्ली

पत्राचार पाठ्यक्रम
दर्शनशास्त्र
प्रारम्भिक 2000/- मुख्य 2500/-

अगर आप भी सफलता सूची में शामिल होना चाहते हैं तो उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए

सम्पर्क करें

Phone : 0532-2611212, 2467642, Mob. : 9839052795, 9415308157

उ०प्र० मुख्य परीक्षा 2002 के परिणाम के 10 दिन बाद साक्षात्कार बैच (U.P. Interview) प्रारम्भ

1183, इस्लाम काम्पलेक्स, मनमोहन पार्क, पुराना कटरा, इलाहाबाद – 211002

प्यासे प्रायद्वीप को जल दान

○ अरविंद घोष

***भा**रत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों का विशाल इलाक़ा सूखे से बराबर त्रस्त रहता है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने इन इलाक़ों तक पानी पहुँचाने की जो अंतर–जलीय सम्पर्क परियोजना तैयार की है, उसके कार्यान्वयन से प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से के बहुत बड़े भू–भाग को पानी के अभाव की समस्या से मुक्ति मिलने की आशा है।*

देश में आम चुनाव के अनेक सकारात्मक पहलुओं में प्रमुख है अनेक समाचार–पत्रों के संवाददाताओं का ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा। इस दौरान उन्हें सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के असंख्य लोगों से सीधी बातचीत के ज़रिए उनकी समस्याओं से रू–ब–रू होने का मौका मिलता है। उनके मानस में चल रही उथल–पुथल की जानकारी प्राप्त करने का अवसर अखबारों के माध्यम से देश भर में अपने पाठकों के सामने उजागर कर सकते हैं। सम्भवतः इस प्रकार के दौरे आम चुनाव के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर संभव नहीं हो पाते।

अंग्रेजी और अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित इस प्रकार की रिपोर्टों से लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी समस्या से अवगत हो सकते हैं जिनका प्रचार बहुत कम होता है। पेयजल के अभाव की कमी हमारे ग्रामीण भारत के बहुत बड़े भाग का खुला दस्तावेज है जिससे पूरे साल का कम–से–कम आधा भाग यानी दिसंबर से मई महीने तक ग्रामीणों को इस समस्या से जूझते रहना पड़ता है। वास्तव में यह कहने में कोई हिचक तो नहीं कि कई राज्यों में लगातार दूसरे अथवा तीसरे वर्ष भी सूखे की भयानक मार ने आम चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि पश्चिम बंगाल का रायगंज एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां सूखे की समस्या ने नहीं, बल्कि बाढ़ की समस्याओं से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। महानंदा नदी की उफनती बाढ़ उस क्षेत्र की आम समस्या है जहां बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि का लगातार बहाव हो रहा है और लोगों के घर–बार उजड़ते चले जा रहे हैं। मार्च महीने में तो काल बैसाख नाम से कुख्यात अवधि में दक्षिण असम में बारक घाटी में इतनी भारी वर्षा हुई कि सिल्चर संसदीय क्षेत्र में निर्धारित मतदान की तिथि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर देने को विवश हो जाना पड़ा।

सूखे से बुरी तरह प्रभावित तमिलनाडु राज्य में भी आश्चर्यजनक रूप से लगभग दो दशक बाद मई महीने के पहले सप्ताह में अप्रत्याशित वर्षा हुई। इससे बीस वर्ष पहले मई महीने के ही दूसरे सप्ताह में इसी तरह की घनघोर वर्षा का उस राज्य पर कहर बरपा था।

वर्षा का यह विकराल रूप सिर्फ़ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निकटवर्ती केरल राज्य में एक सप्ताह तक इस प्राकृतिक कहर का प्रकोप जारी रहा। वैसे यह अलग बात है कि केरल के लिए यह वर्षा वहां सूखे की मार झेल रहे लोगों के लिए वरदान बनकर प्रकट हुई। बाद में घने रूप से केन्द्रित हवा के दबाव ने गुजरात को चक्रवात के भंवर में डाल दिया। वैसे प्रकृति की यह आपदा अपेक्षाकृत कम कृषि योग्य सौराष्ट्र के लिए वरदान बन गई।

वैसे इस प्रकार के प्राकृतिक चमत्कारों से सूखे की जबर्दस्त चपेट में घिरे एक विशाल क्षेत्र की दर्दनाक हकीकत को बदला या झुठलाया नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि पश्चिमी घाटो की पर्वत शृंखलाओं की दृष्टि छाया में पड़ने के कारण पुणे से लेकर बंगलोर से भी आगे तक के क्षेत्र सदियों से अपनी भौगोलिक स्थिति का खामियाज़ा सूखे के रूप में भुगत रहे हैं। सूखा इन क्षेत्रों की सदियों से नियति है और सूखे की भयावहता के साथ ही ये लोग जीते–मरते रहे हैं। सदियों से अकाल से जूझते इन लोगों के चेहरे पर प्राकृतिक आपदा की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जाड़े या गर्मी में दक्षिण महाराष्ट्र से कर्नाटक तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–4 का सफ़र उन क्षेत्रों के लोगों के चेहरे पर सूखे की स्याह सलवटों की जीवन्त दास्तान है

और कोई भी व्यक्ति उनके मूक बयान से इंकार नहीं कर सकता कि उस क्षेत्र में सदियों से जारी प्रकृति की इस विनाशलीला से निपटने के लिए विशेष ध्यान देना ज़रूरी है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि हर वर्ष जुलाई से सितम्बर महीने के बीच दक्षिण–पश्चिम मानसून के महीनों में पश्चिमी तटों के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा होती है। कर्नाटक के अगुम्बे में पश्चिमी तटीय क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा देश भर में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में दूसरे नम्बर पर है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अब चेरापूंजी नहीं, बल्कि मेघालय का मौसिनटम है। इन चार महीनों के दौरान केरल, कर्नाटक, गोवा और पश्चिमी महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पांच हज़ार मिलीमीटर अथवा दो सौ इंच तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है।

इतनी वर्षा? आखिर इतनी वर्षा का पानी जाता कहां है? प्रश्न भले ही जटिल लगे, उत्तर बहुत आसान है। वर्षा का अधिकतर पानी विशाल अरब सागर में समा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र का भू–भाग बहुत संकीर्ण है और पूरे क्षेत्र में न तो कोई बड़ी नदी है और न ही वहां किसी ऐसी आकार–प्रकार की नदी होने की कोई संभावना ही है। हां, अक्तूबर का महीना अवश्य ही वहां के लोगों में खुशी लेकर आता है क्योंकि यही वह समय है जब पहली ख़रीफ़ फसल की कटाई होती है और उसके बाद सारे कृषि–कार्यों पर पूर्णविराम लग जाता है। अगले आठ महीनों तक उस पूरे क्षेत्र में पानी का कहीं कोई नामोनिशान नहीं बचता, मानो पूरी सभ्यता सूखे के चपेट में आ जाती है। वैसे देखा जाए तो वहां अकाल–जैसी कोई स्थिति नहीं रहती लेकिन लोगों के जीवन में व्याप्त ग़रीबी और दरिद्रता को कोई मुखौटा छुपा नहीं सकता। जहां जीवन नहीं, वहां भाव या अभाव दिखे भी तो कैसे। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से शारीरिक रूप से सक्षम सारे लोग, मर्द हों या औरत, अपने घर–बार, चूल्हे–चक्की छोड़कर फ़सल की कटाई के बाद ही आजीविका की तलाश में सदियों से मुम्बई, पुणे अथवा अन्य स्थानों के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी वापसी जून में वर्षा की शुरुआत के साथ ही होती है ताकि मानसून के महीनों में कम–से–कम एक फसल हाथ लग जाए। यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–17 के खुल जाने और कोंकण रेलवे से जो उस क्षेत्र से गुजरती है, वहां की अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिकीकरण की दिशा में भी थोड़ा–बहुत काम शुरू हुआ है।

लेकिन एक दूसरी भयावह सच्चाई यह भी है कि दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र के पूर्वी हिस्से के लोगों को वर्षा का लाभ नहीं मिल पाता। यह अलग बात है कि कभी भाग्य उनका साथ दे जाए लेकिन वे इतने खुशनसीब नहीं और वर्षा का अभाव उन्हें हमेशा त्रस्त करता रहता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए एक उदाहरण पर्याप्त

IAS/PCS - 2004/2005
350+ in 3 months.
समाज शास्त्र
Dharmendra
(Synonyms of Sociology. The Best in India)
राजनीति विज्ञान
Ms. Shubhra Ranjan Saxena
(Go'd Medalist & Lecturer Delhi University)
समकालीन सन्दर्भों को सिद्धान्तों के साथ जोड़कर विषय को अत्यंत रोचक एवं सरल बनाने में सक्षम।
सा० अध्ययन
(स्वयं को बदलते Trend के अनुसार ढालें)
ओम प्रकाश चौधरी, धर्मेंद्र एवं टीम
मनोविज्ञान
(सफलता का अत्यंत सुरक्षित मार्ग। सामग्री की कोई समस्या नहीं।)
ओम प्रकाश चौधरी
GOLD MEDALIST
ADMISSION OPEN
ON FIRST COME FIRST SERVE BASIS
SUBJECT TO CONFIRMATION ON PHONE
AAS
AN IAS ACADEMY
302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
Ph.: 55152590 Cell.: 011-31080722, 33112570

होगा कि वर्ष 2003 में जब दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान सामान्य वर्षा हुई, उस अवधि में महाराष्ट्र के चार दक्षिणी जिलों, कर्नाटक के कोई सोलह उत्तरी जिलों, तमिलनाडु के नौ जिलों और आंध्र प्रदेश के दो जिलों में लगातार दूसरे वर्ष भी आवश्यकता से बहुत कम वर्षा हुई।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गोदावरी के दक्षिण, पूरे दक्कन क्षेत्र में कोई बड़ी नदी नहीं है जो जल स्रोत का सबल साधन बन सके। गोदावरी नदी का उद्‌गम महाराष्ट्र के नासिक के उत्तरी क्षेत्र त्र्यम्केश्वर है। मानसून के दौरान यहां भारी वर्षा होती है। 110.54 बिलियन घन मीटर पानी छोड़ने वाली इतनी विशाल नदी भी गर्मी में सूख जाती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक दूसरी विशाल नदी कृष्णा की सहायक तुंगभद्र और भीम जैसी नदियां है जबकि इन दोनों नदियों की भी सहायक यलप्रभा और घाटप्रभा नदियां हैं। इनके कुल 78.12 बिलियन पानी का विभाजन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच हो जाता है। यह व्यवस्था कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार की गई है। लेकिन प्राधिकरण के निर्णय से ये तीनों राज्य असंतुष्ट हैं और इसे ध्यान में रखते हुए समस्या के निपटारे के लिए यह नया प्राधिकरण जल्दी ही अपना काम–काज शुरू कर देगा।

कावेरी एक अन्य विशाल नदी है जिसकी कुल लंबाई 803 किलोमीटर है और पानी छोड़ने की क्षमता 21.36 बिलियन घन मीटर है। पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी विवाद जग–जाहिर है। प्रायद्वीप में कई छोटी–छोटी नदियां भी हैं जिनकी पानी की क्षमता भी उनके आकार–प्रकार के समान ही कम है फिर भी ये पड़ोसी राज्यों के बीच विवादों से बच नहीं पातीं। इसी प्रकार की एक नदी चित्रावती है जो कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में पेन्नार से मिल जाती है। इस छोटी नदी से पेयजल के विभाजन को लेकर दोनों राज्यों में अच्छा–खासा विवाद चल रहा है।

समाधान

आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या सर्वविदित है और पिछले कुछ समय में इन क्षेत्रों में अकाल का प्रकोप लगातार छाया रहा है। आबादी में वृद्धि और जीवन–स्तर में सुधार के कारण पानी की ज्यादा–से–ज्यादा मांग बराबर उठती रही है। राष्ट्रीय जल विकास निगम द्वारा तैयार की गई अंतर्जलीय संपर्क योजना को कार्यरूप मिल जाने के बाद प्रायद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में काफी हद तक पानी की कमी दूर हो जाएगी क्योंकि दक्षिण–पश्चिम और उत्तर–पूरब, दोनों मानसून के समय उस इलाके में बहुत अच्छी वर्षा होती है। फिर भी पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के पश्चिमी हिस्से का बहुत बड़ा भू–भाग सूखे की चपेट से नहीं बच सकता और वैसी स्थिति में वहां के लोगों के लिए आजीविका

IAS/PCS-2004

CAREER PATH

सिविल सेवा परीक्षा के प्रति समर्पित हिन्दी माध्यम का सर्वोत्तम संस्थान

इतिहास / सा० अध्ययन

द्वारा डॉ० प्रवीण

19 वर्षों के प्रभावी अनुभव के आधार पर अध्यापन।

इतिहास अधुनातन प्रविधियों के आधार पर प्रश्नों का सटीक विश्लेषण।

समाज शास्त्र

भारत के विख्यात समाज शास्त्री द्वारा

राजनीति शास्त्र

द्वारा प्रो. एम.पी. जैन

लोक प्रशासन

द्वारा डॉ. संजीव

10 वर्षों के प्रभावी अनुभव तथा प्रतियोगिता में चयन की रणनीति के आधार पर अध्यापन।

दर्शन शास्त्र

द्वारा प्रो० प्रेम प्रकाश सिंह

Teacher of Mayak Joshi IAS 4th Rank 2002

मनोविज्ञान

द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा

हिन्दी साहित्य

द्वारा प्रो० राज किशोर सिंह

मुख्य परीक्षा के लिए द्वितीय बैच प्रारंभ : 10 - 19 जुलाई

Contact : MR. AMIT KUMAR (Director)

Flat No. 304, A/12, 13, Ansal Building
Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar,
Near Chawla Restaurant, Delhi-110009.
Tel.: 011-30913651, 9891361490

और जीवन का निर्वाह कठिन ही है। उस क्षेत्र के रोजी–रोटी की तलाश में खेतिहर मजूदरों का पलायन उनकी रोजमर्रा की ज़िन्दगी का नियमित हिस्सा है।

इस क्षेत्र में पानी की कमी कैसे दूर की जा सकती है? यह सच है कि सामान्य वर्षापात की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, यद्यपि अप्राकृतिक रूप से बादल उत्पन्न करने के प्रयोग से यदि यह सफल होता है थोड़ी–बहुत वर्षा कराई जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि कृत्रिम उपायों से वहां पानी पहुंचाया जाए। अंतरजलीय परियोजना के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण बात निहित है– दक्षिण कर्नाटक की नेत्रावती नदी को हेमवती से जोड़ने का कार्य। ये दोनों नदियां कर्नाटक के सकलेशपुर क्षेत्र से निकलती हैं। ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां दक्षिण–पूरब मानसून के दौरान पांच हजार किलोमीटर तक वर्षा होती है।

नेत्रावती नदी केरल की सीमा पर मंगलोर से कुछ दक्षिण अरब सागर से मिलती है। हेमवती नदी का प्रवाह सकलेशपुर से दक्षिण की ओर है और यह कावेरी के कृष्णराजसागर जलाशय से मिल जाती है। अंतरजलीय सम्पर्क परियोजना से हेमवती नदी के बहाव में तेजी आ सकती है और इस तरह मैसूर के पास कावेरी से आगे कृष्णराजसागर जलाशय में पानी बढ़ सकता है।

लेकिन बेदती–वरदा सम्पर्क को छोड़कर पश्चिमी घाटों के पूरब में पश्चिमी ढलानों में पानी के सीमित विभाजन की भी अब तक कोई योजना नहीं बनी है। हां, इस योजना से पश्चिम की ओर कर्नाटक के गोकर्ण से भीतरी उत्तरी कर्नाटक में वरदा तक जो अरब सागर से मिलती है, तुंगभद्र कमान क्षेत्र के लिए पानी के बहाव का रूख किया जा सकता है। चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित ही है कि इस प्रकार की दोनों योजनाओं का उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र क्षेत्रों में कोई ख़ास असर नहीं हो सकता। इसकी सफलता के लिए एक अलग योजना की जरूरत है जिसमें यह व्यवस्था हो कि पश्चिमी तटों पर पश्चिमी हिस्से में दक्षिण–पूर्व मानसून के चार महीनों में जितनी ज्यादा वर्षा होती है, उन्हें जमा कर लिया जाए और इस तरह एकत्र किए गए पानी को पहाड़ियों पर पंपिंग अथवा सुरंगों के जरिए वर्तमान नदियों तक पहुंचाया जाए। जो दक्षिण–पश्चिम मानसून के खत्म होते ही पलक झपकते सूख जाते हैं। ऐसा विचार जोर पकड़ रहा है कि इस क्षेत्र में नई सिंचाई योजनाएं शुरू किए बिना वहां के लोगों के पलायन और वहां की आर्थिक स्थिति में वांछित सुधार संभव नहीं है। इस तरह की योजनाओं से उन नदियों से बराबर पानी मिलता रहेगा जो अचानक सूख जाती हैं। हमारे भारतीय इंजीनियर इस प्रकार की योजना को कार्यरूप देने में पूरी तरह सक्षम हैं। स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारतीय इंजीनियरों ने सिंचाई के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, वे ऐतिहासिक हैं और हमारे देश की महान गौरवपूर्ण परम्परा की श्रृंखला की यादगार मिसाल हैं। यदि जमा पानी को वांछित स्थान तक पहुंचाने के लिए पम्पिंग की जरूरत हो, तो उसके लिए पश्चिमी घाटों के पूरबी ढलानों से छोटी नदियों और नालों में गिरने वाले पानी से ही बिजली पैदा की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में अजुधिया नदी परियोजना की ही तरह पम्प स्टोरेज सिस्टम भी तैयार हो सकता है। अगर योजना के लिए पहाड़ियों के काफी ऊंचे स्थानों का चुनाव किया जाए तो पानी को ऊपर तक लाने के लिए भी कोई खास प्रयास नहीं करना होगा और इस प्रकार बिजली की खपत भी ज्यादा नहीं होगी।

अगर ये योजनाएं वास्तविकता का रूप ले लें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रायद्वीपीय भारत में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा और पम्पों पर होने वाले बिजली के खर्च को पूरा करने में ये स्वयं सक्षम होंगी।

पानी पहुंचाने वाली सुरंगों का निर्माण खर्चीला हो सकता है लेकिन भारतीय इंजीनियर देश के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की सुंरगें तैयार करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हिमाचल में पन्डोह और देहर के बीच व्यास–सतलुज सम्पर्क योजना और हाल ही में पूरी की गई नाथपा झाकरी पन–बिजली योजना के हिमालय के रास्ते लंबी–लंबी सुरंगों का निर्माण हमारे इंजीनियरों की कार्यकुशलता का प्रमाण है। कोंकण रेलवे मार्ग में ही नब्बे किलोमीटर लंबी सुरंगे हैं जिनमें रत्नागिरी के दक्षिण करबुडे में साढ़े छह किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है।

ध्यातव्य है कि हर वर्ष वर्षा से भारत को मिलने वाले 4 हजार बिलियन घन मीटर पानी में हिमपात से प्राप्त जल भी शामिल है। 1100 बिलियन घन मीटर पानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। अंतर्जलीय परियोजना के लिए इसका बहुत थोड़ा–सा भाग यानी सिर्फ ढाई सौ बिलियन घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। बाकी पानी पहले की ही तरह सागर में जाता रहेगा ताकि उन नदियों को बराबर पानी मिलता रहे और उनमें उत्पन्न होने वाले पेड़–पौधों और जीव–जन्तुओं के लिए आवश्यक मात्रा में पानी मिलता रहे जिन पर पानी जमा करने के बांध निर्मित हैं अथवा जिनके निर्माण का प्रस्ताव है। पश्चिमी तटों से पूरब की ओर पानी के स्थानान्तरण के लिए जितने पानी का प्रस्ताव किया गया है, उसकी मात्रा अत्यंत सीमित है और इसका कोंकण के नाम से प्रख्यात पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों के अनेकानेक छोटी–छोटी नदियों में जल–प्रवाह में किसी प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ेगा। ❑

(लेखक हिन्दुस्तान टाइम्स के पूर्व संवाददाता हैं)

हमारे टॉपर्स

Amritendu Sekhar
BPSC 2nd Topper

"सर के G.S. पढ़ाने-समझाने एवं अभिभावक की तरह मार्गदर्शन का तरीका अद्भुत है"

Ajay Kumar
BPSC 8th Topper

ILA G. PARMAR
IAS 2003 (393 Rank)

SC/ST/OBC एवं महिलाओं के लिए संवर्द्धन (NGO) प्रायोजित शुल्क रियायत सुविधा

झारखंड एवं हरियाणा PCS (MAINS) के अनुरूप G.S. एवं इतिहास का श्रेष्ठ पत्राचार सामग्री 10 मई से उपलब्ध

हमारे टॉपर्स

Shashi Bhusan Singh
UPPCS Topper

"G.S. और इतिहास मेरे लिए सबसे अंकदायी रहा इसका सम्पूर्ण श्रेय सर को जाता है।"

Sunil Kumar Agarwal
IAS 2003 (317 Rank)

G.S.

IAS/PCS (फाउंडेशन + मुख्य + प्रारम्भिक) + टेस्ट सीरिज + मानक प्रश्न-उत्तर प्रारुप कक्षाएँ

वैकल्पिक विषय के रूप में / इतिहास / का वैज्ञानिक तरीके से अध्यापन जिससे प्री० में 90 से 100 प्रश्न सही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 350 अंक

By

R. Kumar & Team

बैच प्रारम्भ : 15 जुलाई एवं 1 अगस्त

Updated जीवंत पत्राचार

सामान्य अध्ययन :-
मुख्य परीक्षा - 6 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 6 Booklet
इतिहास :-
मुख्य परीक्षा - 2 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 3 Booklet
हिन्दी साहित्य - 3 Booklet

Science & Tech. by R. Kumar IAS TUTORIALS
Economics by R. Kumar & Team IAS TUTORIALS
Indian Polity by R. Kumar IAS TUTORIALS
History by R. Kumar IAS TUTORIALS
G. Science by R. Kumar IAS TUTORIALS
...

शुल्क एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें:-

अन्य विषय	इतिहास द्वारा आर. कुमार	समाज शास्त्र द्वारा डॉ० एस.आर. सिंह	हिन्दी साहित्य द्वारा राजेश कु० राजन	लोक प्रशासन द्वारा मनीषा सिंह	Zoology द्वारा D.U. Prof.

आवासीय सुविधा उपलब्ध

आस्था IAS TUTORIALS

HEAD OFFICE :
102-103, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392 Cell.: 9810664003

1 मई, 2004 से IAS TUTORIALS का नया नाम आस्था IAS TUTORIAS हो गया है।

11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पर विशेष

जनसंख्या विस्फोट का दुष्चक्र : कारण और निवारण

○ सुकन पासवान प्रज्ञाचक्षु

जब चीन जैसे विशालतम जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आ रही है तो भारत में यह प्रवृत्ति वृद्धिनोत्मुख क्यों है? जब तक इस विकट दुष्चक्र का हम समाधान तलाश नहीं लेते तब तक एक ठोस एवं व्यावहारिक जनसंख्या नियंत्रण उपाय की तलाश अधूरी ही मानी जाएगी।

वर्तमान में सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न अग्रणी विकासशील देशों की श्रेणी में चीन और भारत जैसे देशों के लिए जनसंख्या विस्फोट का है; जबकि जनसंख्या ही किसी देश के आर्थिक दिल की धड़कन के समान होती है। उत्पादन एवं समग्र आर्थिक गतिविधियों की धुरि मानव संसाधन का परिसम्पत्ति के बदले दुष्चक्रीय समस्या के रूप में परिणत हो जाना अपने आप में एक विरोधाभासी है। गंभीर प्रश्न यह है कि जब चीन जैसे विशालतम जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आ रही है तो भारत में यह प्रवृत्ति वृद्धिनोत्मुख क्यों है? जब तक इस विकट दुष्चक्र का हम समाधान तलाश नहीं लेते तब तक एक ठोस एवं व्यावहारिक जनसंख्या नियंत्रण उपाय की तलाश अधूरी ही मानी जाएगी।

वर्तमान में भारतीय जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर लगभग दो फीसदी है जबकि चीन की लगभग एक फीसदी। स्वाभावतः यह आंकड़ा उल्टा होना चाहिए था जबकि स्थिति इसके विपरीत है। इसका अर्थशास्त्रीय उत्तर यह है कि चीन विकसित देश की श्रेणी में सम्मिलित होने की स्थिति में है और हम अर्द्धविकसित देशों की ओर उन्मुख हैं क्योंकि विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः घटती जाती है और अर्द्धविकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जाती है। इससे यह अपने आप सिद्ध होने लगता है कि हमारे आर्थिक विकास की दिशा प्रतिगामी प्रवृत्ति की होती जा रही है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि हमारी सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में एक बहुत बड़ा अंतर होता जा रहा है। दिखने को एक ओर गिने–चुने, बड़े–बड़े, आधुनिक आविष्कार पर आधारित उद्योग स्थापित हो जा रहे हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में शरीरस्थ तंत्रिका–तंत्रों की तरह फैले छोटे, मंझोले तथा कुटीर उद्योगों में तीव्रता से ह्रास हो रहा है। जिस तरह बिना औजार के कोई काम नहीं होता; ठीक उसी तरह बिना काम का आदमी केवल अनुत्पादक जनसंख्या की संख्या बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण की सारी नीति हाथी दांत के समान सिद्ध होती है।

यहां यह उद्धत करना अप्रांसगिक नहीं होगा कि चीन ने यह उपलब्धि अपने वृहद उद्योगों में लघुकरण एवं विस्तारीकरण के रास्ते हासिल की है और भारत ठीक इसके विपरीत प्रवृत्ति के कारण पिछड़ गया है। भला यह विचारणीय प्रश्न नहीं है क्या कि जिन जिन्सों का आयात चीन को हमसे करना चाहिए था उन्हीं वस्तुओं के निर्यात के लिए वह हमसे मैत्री का मायाजाल फैलाकर बाजार मांग रहा है? इसका मतलब साफ है कि उसने अपने यहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जाल बिछाकर न केवल बेकार हाथों को काम दिया है बल्कि खाली पेटों को भरकर जनसंख्या वृद्धि के खिलवाड़ को रोकने का सफल उपाय किया है।

आज चीन निर्यातक की स्थिति में इसलिए आ गया है क्योंकि वह अपने पास उपलब्ध अन्य संसाधनों के साथ–साथ विपुल मात्रा में उपलब्ध मानव

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास
रजनीश राज

रजनीश सर पत्थर में छिपी मूर्ति की सम्भावना को तराशने की कला जानते हैं।

Manoj Tewari
62nd Rank :UPSC-2002
Marks in History : 358

इतिहास में पढ़ा था कि हर्षवर्धन को कार्य करने से ही उर्जा मिलती थी। रजनीश सर को देखकर ही लगा कि ऐसा भी संभव है।

Alok Jaiswal
Selected for D.S.P. (UP) 2001

विशिष्टः हम आपको इतिहासकार नहीं प्रशासक बनाते हैं। कैसे?

मुख्य परीक्षा

- सुसंगत पाठ्यक्रम प्रबन्धन।
- यथोचित रणनीतिक मार्गदर्शन।
- 150 प्रश्नों का वैज्ञानिक मूल्यांकन।
- आकस्मिक एवं सावधिक टेस्ट।
- आदर्श उत्तर लेखन के लिए प्रारूप तकनीक।
- संक्षिप्त प्रश्नों एवं मैप पर विशेष बल।
- जानिए कि एक-2 अंक कैसे बढता है।

प्रा० परीक्षा

- तथ्यों के अम्बार से नहीं बल्कि श्रेष्ठ चयन पर आधृत।
- पुनरावृति नहीं, संगत पुनरावलोकन।
- 35 सावधिक टेस्ट।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर पुनरावलोकन।
- यथेष्ट सामग्री।

इस वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन

दिलीप पाण्डेय -360
आलोक जायसवाल -340
रमेशचन्द्र त्रिपाठी -335
25 अन्य 300 से अधिक अंक

अतिरिक्त : निबन्ध एवं साक्षात्कार के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन

नामांकन प्रारम्भ

SIHANTA IAS

632, Mukherjee Nagar, Delhi-9
(Near Aggarwal Sweets)
9810969605

भारतीय कृषि का मूलाधार – मानसून पवन

❍ राधाकान्त भारती

विख्यात वैज्ञानिक एडमंड हैली उन पहले वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने सन् 1686 में मानसून की प्रक्रिया की एक वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार गर्मी के समय जब महाद्वीप खूब तप जाता है तो वायु गरम होकर फैलती है और ऊपर उठती है। परिणामस्वरूप पूरे इलाके में हवा का दबाव घटता है और समुद्र की शीतल, नमी प्रधान वायु तेजी से इन निम्न दबाव वाले क्षेत्र में घुसकर सूखे मैदानी इलाके में बारिश लाती है।

पुराने समय में लोगों को यह मालूम नहीं था कि मानसून साल–दर–साल क्यों आता है, किंतु उन्होंने इन हवाओं का फायदा जरूर उठाया। शीतकाल में सामान्यतः उत्तर–पूर्वी व्यापारी हवाओं के सहारे भारत से अफ्रीका–अरब देशों तक व्यापारी जलयानों से जाते थे और जून–जुलाई की मानसूनी हवाओं पर लौटते थे। व्यापार और कृषि के संदर्भ में मानसून के आवागमन का पता लगाना लोगों के लिए जरूरी था। इसका अंदाज वे विभिन्न पौधों, जानवरों एवं पक्षियों के व्यवहार में अंतर से लगाते थे। सोलहवीं शताब्दी में अरब ने वैज्ञानिक तरीके से इसके आगमन का अनुमान लगाने की कोशिश की थी। 'मानसून' शब्द का उद्भव भी अरबी लफ्ज़ मौसम से हुआ है।

विख्यात वैज्ञानिक एडमंड हैली उन पहले वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने सन् 1686 में मानसून की प्रक्रिया की एक वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार गर्मी के समय जब महाद्वीप खूब तप जाता है तो वायु गरम होकर फैलती है और ऊपर उठती है। परिणामस्वरूप पूरे इलाके में हवा का दबाव घटता है और समुद्र की शीतल, नमी प्रधान वायु तेजी से इन निम्न दबाव वाले क्षेत्र में घुसकर सूखे मैदानी इलाके में बारिश लाती है, जबकि सर्दियों में इस प्रक्रिया का ठीक उल्टा होता है।

मानसूनी हवाएं हिंद महासागर के सुदूर दक्षिणी भाग से चलती हैं और एशिया के मध्य में स्थित निम्न वायु–भार के क्षेत्र में पहुंचने के लिए इन्हें विषुवत रेखा पार करनी पड़ती है। फलस्वरूप पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभाव से यह उत्तर–पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आरंभ में मानसून की अरब सागर वाली शाखा केरल तट पर तथा दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी शाखा बंगाल तट पर पहुंचती है। यहां से भारत उपमहाद्वीप में बरसात की शुरुआत होती है। भारत में मानसूनी वर्षा का सबसे विचित्र पहलू यह है कि किसी इलाके में भले ही पिछले साल की अपेक्षा कम या ज्यादा बारिश हो, किंतु पूरे देश में मानसूनी वृष्टि की कुल जलराशि प्रायः एक–सी रहती है। इसका अर्थ यह है कि एक क्षेत्र में कम वर्षा का कारण दूसरे क्षेत्र में अधिक जल वर्षा का होना है। मानसून के इस रहस्य का पता आंकड़ों के निरंतर विश्लेषण के बाद मिला है। भारत में सूखा और बाढ़ दोनों स्थितियों को लाने वाला यह मानसून ही है। ऐसी विचित्रता के कारण ही प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में किसी हिस्से में वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति पैदा होने से हाहाकार मच जाता है, सारा कृषि कार्य रूक जाता है तो दूसरी ओर अधिक वर्षा से नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है, खेत में खड़ी फसलें बह जाती हैं और धन–जन की अपार क्षति होती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का यह मानसूनी खेल कृषकों के लिए विकट संकट उत्पन्न कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत के किसानों को मानसूनी बरसात की ऐसी अनिश्चित स्थिति का कोई समाधान नहीं मिल पाया है। अपनी मस्ती और मतवाली चाल के लिए मानसून काफी बदनाम है।

मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कृषि प्रधान देश भारत में खेती–बाड़ी के काम में उतार–चढ़ाव होता रहता है। मानसून पर अधिक निर्भर होने के

(शेषांश पृष्ठ 52 पर)

शुक्र ग्रह का पारगमन

○ शैलेन्द्र मोहन कुमार

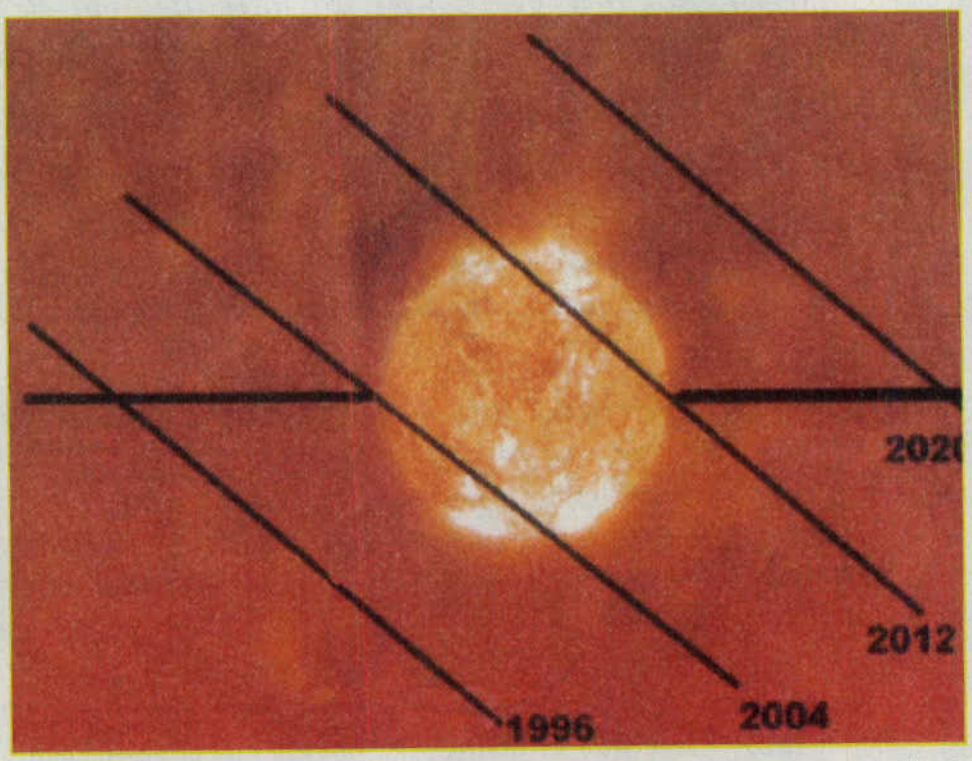

खगोल के इतिहास में 8 जून, 2004 एक अविस्मरणीय दिन रहेगा। उस दिन शुक्र ग्रह ने सूर्य के सामने से 122 वर्ष के बाद पारगमन किया। इस घटना को पूरी दुनिया में देखा गया। वेधशालाओं और खगोल प्रतिष्ठानों में इस घटना के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तो पहले से ही विशेष प्रबंध किए गए थे। सामान्य आदमी भी इसके प्रति बहुत उत्साहित था। इसीलिए पारगमन के निर्धारित समय से बहुत पहले ही लोग उन तारामंडलों और वैज्ञानिक शिक्षण संस्थानों के परिसरों में उमड़ने लगे थे जहां से यह अद्भुत खगोलीय घटना देखी जा सकती थी। भारत में तो मानो उत्सव का ही दृश्य था। जिसकी उन्हें बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ऐसा होता भी क्यों नहीं? शुक्र ग्रह का सूर्य के प्रभा मंडल के साक्षात् आरपार जाना कोई मामूली घटना तो नहीं थी!

सौर मंडल में शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर है। सूर्य के बाद पहला ग्रह बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए वहां सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में दिखेगा। यह ग्रह बहुत चमकीला दिखाई देता है। इस कारण इसे 'शाम का तारा' भी कहा जाता है। अमेरिका अंतरिक्ष यान मैजेलेन ने इसका विस्तृत नक्शा तैयार किया है। शुक्र ग्रह का परिक्रमा–काल पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा है। शुक्र के सौर पारगमन की बात एक अद्भुत बात है। यह घटना जोड़ों के हिसाब से होती है। एक बार 105 वर्षों के अंतराल पर और फिर 8 तथा 122 साल बाद। खगोलशास्त्र के अनुसार यह घटना सूर्य ग्रहण के ही समान है। अंतर केवल इतना है कि सूर्य के निकट का यह ग्रह चंद्रमा के स्थान पर खुद पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर उसके चमकीले मुख पर एक चलायमान काले धब्बे के रूप में देखा जाता है।

आठ जून को इस सहस्त्राब्दी की यह पहली घटना थी। जो इसे नहीं देख सके उनके लिए दुबारा अवसर 6 जून, 2012 में एक बार फिर आएगा। इसके बाद ऐसा पारगमन सन् 2117 में ही दिखाई देगा। तब तक न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी।

आठ जून, 2004 को शुक्र का पारगमन पूरे भारत में देखा गया। हां, कहीं–कहीं रुकावटें भी आईं। जैसे धूल भरी आंधी, तूफान, मेघ, वर्षा और हिमपात। फिर भी सभी संतुष्ट थे। टेलीविजन ने दुनिया के प्रत्येक भाग से इस अद्वितीय खगोलीय घटना के दृश्य हमें दिखाएं। अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया में लोगों ने संपूर्ण पारगमन देखा। अमेरिका के उत्तर–पूर्वी कोने और कनाडा में लोगों को इस अलौकिक घटना के अंतिम चरण का ही दृश्य देखकर संतुष्ट होना पड़ा जो पिछली बार उनके पूर्वजों ने सन्

1882 में देखा होगा।

सन् 1716 में इंगलैंड के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक सर एडमंड हैली ने इस घटना को देखकर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापी थी। इतिहास में इसका वर्णन सन् 1631 से मिलता है। इसकी पुनरावृत्ति सन् 1639 में हुई। उसके बाद ऐसे पारगमन सन् 1761 और 1769 तथा सन् 1874 और 1882 में देखे गए। 8 जून, 2004 और 6 जून, 2012 के 105 साल बाद यानी 2117 और सुदूर भविष्य में सन् 2225 में शुक्र ग्रह का पारगमन फिर होगा।

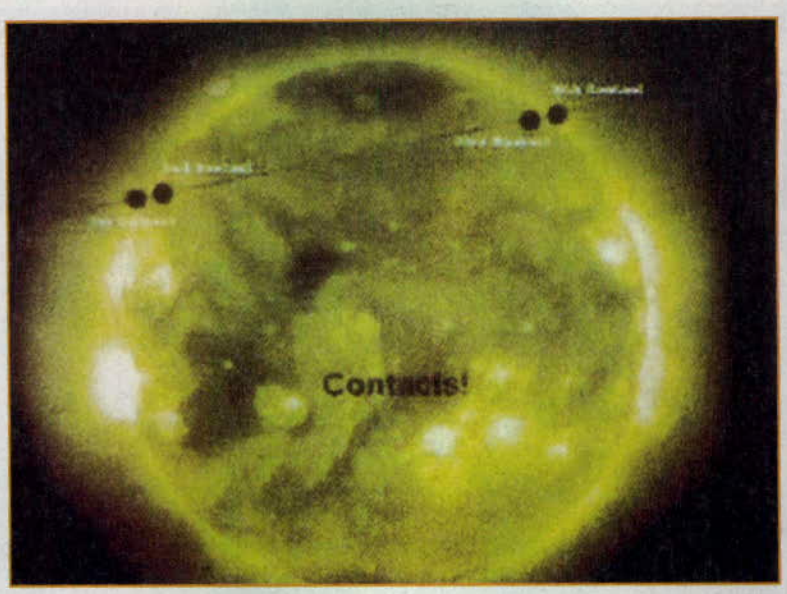

यूनानी तथा रोमन दंत कथाओं में शुक्र ग्रह को प्रेम का देवता माना गया है। लगभग पृथ्वी के ही आकार का होने के कारण खगोल वेत्ताओं को इसके अध्ययन में कभी विशेष रुचि हुआ करती थी। लेकिन अब वे मंगल ग्रह के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हर समय प्रचंड रूप से उतप्त और गंधकीय अम्ल युक्त वातावरण होने के कारण शुक्र ग्रह का अनुसंधान दुष्कर है। यदि इसके निर्माण–काल अथवा उसके बाद वहां किसी भी रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो अब निश्चित रूप से उसका कोई चिह्न नहीं मिलता। सारे प्रमाण मिट चुके हैं क्योंकि शुक्र ग्रह के 460 डिग्री सेल्सियस तापमान में कुछ भी नहीं बच सकता। अमेरिकी एजेंसी नासा तो अब वहां किसी भी अंतरिक्ष यान को नहीं भेज रही है। लेकिन यूरोपीय और जापानी अंतरिक्ष संगठनों ने कहा है कि वे अपने यान निकट भविष्य में शुक्र ग्रह के और व्यापक अनुसंधान के लिए अवश्य भेजेंगे। ❑

(विज्ञान लेखक)

IAS (वैकल्पिक विषय एवं सामान्य अध्ययन) PCS
J अर्थशास्त्र N
R द्वारा E
F आनन्द शुक्ला T
★ JRF/NETका अलग बैच
★ सम्पूर्ण नोट्स
★ मॉडल पेपर द्वारा अभ्यास
★ छात्रावास सुविधा उपलब्ध
★ पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध
बैच प्रारम्भ नामांकन जारी
आनन्द एकेडमी
13/3, बन्द रोड, इलाहाबाद ● फोन : 0532-2466692, 9415254465

Y.D. Misra's IAS

ADMISSION OPEN *for*

IAS Main-2004

IAS Main-cum-Prelim-2005

(Hindi & English Medium)

Dr. Mukherjee Nagar Centre

HISTORY

by Y D Misra

"An experience of 38 yrs."

Special features:
- PCS Syllabus of UP, MP, Uttaranchal Bihar and Rajasthan also covered
- Discussion and revision sessions
- Regular Tests for developing your writing skills
- Focussed study material

For further enquiry please contact: Manoj K singh (Director: MIPS Education)

Y.D.Misra's IAS

C/o MIPS Education, B-19, Satija House Commercial Complex, Near UTI ATM, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi-9

Ph.27652738, 27651700, Cell:9810345023

East Patel Nagar Centre

HISTORY *by* **Y D Misra**

Pub. Admn *by* **Ajay P. Sharma**

Sociology *by* **Jaya Misra Sharma**

Pol. Sc. *by* **Eminent Faculty**

General Studies

(A very special package by Y.D. Misra & Experts)

Most ultramodern infrastructure
Unbelievable library facility

Y.D. Misra's IAS

30/27,East Patel Nagar, New Delhi-8 (Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road) Ph. 55486332/55486334/55486335

Postal guidance

Only at Y.D. Misra's IAS East Patel Nagar Centre

G.S., Hist., Pub. Ad., Sociology

(Each subject for Rs. 1600)

A unique series of Previous years IAS Main/Prelim question Papers along with topicwise analysis available. GS question papers for Rs. 100 and IAS optional subjects for Rs. 70 each.

Y.D. Misra's IAS

30/27,East Patel Nagar, New Delhi-8

(Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road) Ph. 55486332/55486334/55486335

ज्ञान-सागर

→ राडार का आविष्कार बीसवीं शताब्दी में हुआ। यह अविष्कार स्काटलैंड में हुआ था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक राबर्टवाटसेम इसके अविष्कारक हैं।

→ जेम्स नेग सिम्पसन ने क्लोरोफार्म का अविष्कार उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में किया।

→ दूरदर्शन का अविष्कार बीसवीं सदी में हुआ। इसके अविष्कार का श्रेय स्काटलैंड के एक पादरी युवक जन लोनी को जाता है।

→ टेलीफोन का अविष्कार उन्नीसवीं सदी के अंत में हुआ। इसके अविष्कारक का नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। यह स्काटलैंड का रहने वाला एक महान वैज्ञानिक था।

→ टेपरिकार्डर का अविष्कार कोपेहेगन के एक वैज्ञानिक बाल्टे मैर पोक्सन ने किया था।

→ उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड के एक इंजीनियर ने टैंक का अविष्कार किया जिनका नाम जॉनफेन्डिर था।

→ थर्मामीटर का अविष्कार सोलहवीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक गैलिलियों ने किया था।

→ फ्रांस के काडेनिस पेपिन ने प्रेशर कुकर का अविष्कार किया।

→ माइक्रोस्कोप का अविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलिलियों ने किया।

→ राकेट का अविष्कार बीसवीं सदी के आरंभ में रूस के एक वैज्ञानिक सियोल्फोवस्की ने किया।

→ जर्मनी के एक इंजीनियर 'कार्ल्ड बैन्च' ने पेट्रोल इंजन और गैस इंजन बनाया जिसे मोटरकार में इस्तेमाल कर मोटरकार बनाई।

→ रेडियम पिसे हुए नमक के चूर्ण के सामान होता है। पृथ्वी पर यह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसका मूल्य सोने से कई गुणा अधिक है। रेडियम की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बेकेरिज द्वारा सन् 1896 में की गई।

→ मानव मस्तिष्क अखरोट की शक्ल का होता है जो नाजुक गुलाबी, स्लेटी रंग का होता है। एक सामान्य मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। मस्तिक में करीब 10 अरब कोशिकाएं होती हैं।

→ वैज्ञानिक उपग्रहों द्वारा सूर्य द्वारा प्रदत ऊर्जा आयन मंडल में सूर्य के अस्त होने से होने वाले परिवर्तन, मंगल, शुक्र, वृहस्पति आदि ग्रहों के चारों ओर का वातावरण आदि के विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।

→ मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले पार्थिव उपग्रहों को मौसमी उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर स्थित इन मौसमी उपग्रहों में लगे यंत्र बादलों के आर–पार की मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। मौसम संबंधी सटीक पूर्व जानकारी देने के कारण ये उपग्रह प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने में सहायक होते हैं।

→ दूरसंवेदी उपग्रह की सहायता से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी वस्तु से उत्पन्न होने वाले प्रतिबिंबित होने वाले विकिरणों को प्रकाश एवं इन्फ्रा–रेड किरणों का उपयोग करने वाले सूक्ष्म कैमरों तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा नीले–लाल, नीले–हरे एवं लगभग इन्फ्रा–रेड कणों के चित्रों के रूप में लिया जा सकता है। दूरसंवेदी उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों से खनिज, कृषि, वानिकी, सागर संपदा आदि से संबंधित विषयों पर शीघ्रता से उपयोगी एवं सटीक जानकारी उपलब्ध होती है।

→ मैरीसेट उपग्रह समुद्री जलयानों के नाविकों को संकट की प्रत्येक घड़ी में रेडियों संकेतों द्वारा दिशा ज्ञान और निर्देश देते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों से वे दूसरे जलयानों के नाविकों एवं अपने मुख्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

→ तुल्यकालिक उपग्रह उन उपग्रहों को कहा जाता है जो कि एक दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के एक क्षेत्र विशेष के ऊपर स्थित प्रतीत होता है।

→ भू–प्रक्षेपण उपग्रह अपने सूक्ष्म कैमरों एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मदद से पृथ्वी के विभिन्न भागों के चित्र लेते रहते हैं। इनके द्वारा पृथ्वी के गर्भ में छिपी प्राकृतिक संपदाओं की भी खोज की जाती है। समुद्री लहरों एवं तूफानों के कारणों का भी पता भू–प्रक्षेपण उपग्रह लगाते हैं। इन्हें टोहक उपग्रह भी कहा जाता है।

→ भू–स्थिर उपग्रह पृथ्वी के किसी स्थान विशेष के सापेक्ष स्थिर रहते हैं। इन उपग्रहों का उपयोग दूरभाष, टेलीविजन सिग्नलों आदि के संचार में होता है। यदि इस प्रकार के तीन उपग्रह भू–स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाएं तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण पृथ्वी से एक साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है।

(संकलन : सरिता कुमारी)

द हिस्टोरिका

IAS — PCS

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित संस्थान

'मुख्य-परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक् प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है।'

मुख्य-परीक्षा-2004 पर केन्द्रित विशेष कक्षा कार्यक्रम

नामांकन प्रारम्भ

इतिहास: रमेश चन्द्रा के दक्ष मार्गदर्शन में। 14 जुलाई, 5 अगस्त

सामान्य अध्ययन : रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ। 15 जुलाई, 6 अगस्त

निबन्ध : अगस्त के अन्तिम सप्ताह में 10 दिवसीय कार्यक्रम

फाउण्डेशन कोर्स-I.A.S.- 2005

इतिहास एवं सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक+मुख्य परीक्षा) के लिये

यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी अभी शुरु नहीं की है या तैयारी की प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

☞ विस्तृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें : **9818391120 (8 P.M. To 10 P.M.)**

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का संयोजन दूर स्थित विद्यार्थियों एवं क्लास-कोचिंग लेने में असमर्थ विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है।

विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास

विशेषताऐं:

- अध्ययन सामग्री को मुख्य परीक्षा 2004 के लिए संशोधित कर दिया गया है।
- विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर जाँच की डाक द्वारा व्यवस्था।
- कार्यक्रम में नामांकित छात्रों की समस्याओं का सीधे 'रमेश चन्द्रा' सर के द्वारा साप्ताहिक निवारण। दिन : रविवार, समय : 8 P.M. To 10 P.M., Mob. No. : 9818391120

फीस: मुख्य परीक्षा - 2500/- रुपये मात्र। प्रारम्भिक परीक्षा - 2000/- मात्र,

नोट: कार्यक्रम में नामांकन हेतु दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट 'रमेश चन्द्रा' के नाम निम्न पते पर भेजें।

2063(BASEMENT), OUTRAM LINES, KINGSWAY CAMP, DELHI- 9 TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

सफलता–असफलता

❍ ज़ियाउर रहमान जाफ़री

प्रत्येक मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह कठिन से कठिन परिश्रम करता है। असफलता उसमें हताशा पैदा करती है और सफलता से उसमें आत्म–विश्वास बढ़ता है। सफलता एक ऐसा व्यापक शब्द है जिस तक पहुंचने के लिए हमें कई प्रक्रियाओं, कई सोपानों से गुज़रना पड़ता है। कड़ी मेहनत और मशक़्क़त करनी पड़ती है। सफलता के लिए सबसे आवश्यक है संकल्प शक्ति, निष्ठापूर्ण परिश्रम और कुछ कर गुज़रने की चाहत। हिमालय का यह विशाल पर्वत न जाने कब से खड़ा है, लेकिन उस उत्तुंग शिखर तक पहुंचने की हिम्मत एडमण्ड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग ने ही जुटाई और इतिहास में अमर हो गए। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपना भाग्य लेकर नहीं आता। हम जिसे भाग्य कहते हैं वह इसी धरती पर उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। सफलता– प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है कि मनुष्य सर्वप्रथम अपनी रूचियों, संभावनाओं और क्षमताओं का अध्ययन करे, तत्पश्चात् नियमित अभ्यास करते हुए पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करे। हमें यह आत्मसात् कर लेना चाहिए कि निरन्तर अभ्यास सफलता का सूत्र है और आलस्य तथा कोताही इस पथ का सबसे बड़ा शत्रु है। खरगोश और कछुए की प्रसिद्ध कहानी में खरगोश छलांगें तो मारता था किंतु बीच में आलस्य

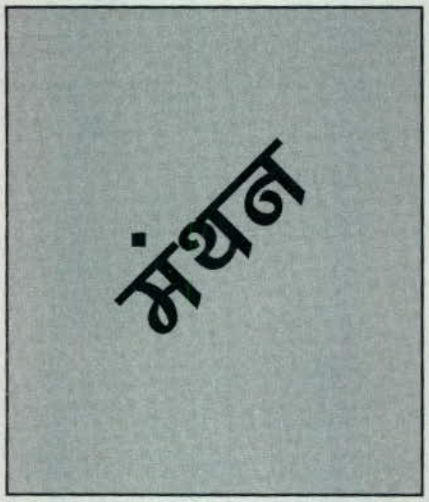

में आकर सो जाता था इसके विपरीत कछुआ धीमी चाल से निरंतर चलता रहा और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजयी हुआ। कहा भी गया है – मंद गति से सतत तथा नियमित कार्य करने वाला व्यक्ति विजयी होता है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सफलता का कोई शार्ट–कॉट रास्ता नहीं होता। इसके लिए दृढ़तापूर्वक नियमित रूप से परिश्रम करना लाज़मी है। किंतु होता यह है कि हम पूरी निष्ठा से उद्यम नहीं करते। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य उस मछली की आंख पर नहीं होता। हमारी स्थिति अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करने की नहीं होती। हम अपनी असफलता का कारण खोजते हुए कभी भाग्य को, कभी काल को तो कभी परिस्थितियों और ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। ऐसे व्यक्ति कायर की श्रेणी में आते हैं। जेम्स जायस नामक उपन्यासकार का कथन बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति को सफलता अपनी वजह से मिलती है, समय–स्थान या परिस्थितियों से नहीं। आपने चींटी वाली वह कहानी तो सुनी ही होगी जो बार–बार ऊंचाई से गिरकर भी शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो गई। यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पहली की दफा में सफलता प्राप्त कर ले। कहा भी गया है कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। असफलता के बाद भी सफल हो जाने वाले प्रत्याशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी गलतियों से सीख लेता रहे, और तदनुरूप नई रणनीति के साथ परिश्रम भी करता रहे। किसी ने कहा भी है– असफलता सफलता से मात्र एक पग पीछे रह जाती है। जीवन में सफलता का यह सूत्र स्मरणीय है कि– असफलता के बाद भी आत्मविश्वास न खोना और इस दिशा में प्रयत्नशील रहना ही सफलता का रहस्य है। निर्वासित एकाकी श्रीराम ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ही अहंकारी रावण को परास्त किया था। हमें जितनी बड़ी सफलता की अपेक्षा है हमें उसके अनुकूल परिश्रम भी करना चाहिए। एवरेस्ट पर्वत तक पहुंचने के लिए हमको हिलेरी, दृष्ट और शेरपा तेनसिंग की भांति तैयारी भी करनी होगी। चांद तक पहुंचने के लिए नील आर्मस्ट्रांग बनना होगा। हमें गुलाब के फूल तक पहुंचने के लिए कांटों का सामना करना ही होगा। इस प्रयत्न में कांटे भी चुभ सकते हैं, लेकिन ऊंचे मूल्यों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों के बीच यह

जटिलताएं–कठिनाइयां अधिक देर तक आड़े नहीं आती।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने इसी को लक्ष्य कर एक स्थान पर लिखा है–

मुश्किलें दिल के इरादे आज़माती हैं
स्वप्न के परदे निगाहों से हटाती है
हौसला मन हार गिरकर ओ मुसाफ़िर
ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं

संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव है। नेपोलियन अक्सर कहा करता था कि संसार में कुछ भी करना असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि– असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। एक बार नेपोलियन की सेना आल्प्स पर्वत के पास जाकर रुक गई, नेपोलियन ने आवाज़ लगाई – आल्प्स है ही नहीं और सेना पर्वत के पार हो गई। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग सफलता को अवश्यंभावी बनाता है। हमारे पास ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब व्यक्ति ने उत्साह के बल पर मनोवांछित सफलता प्राप्त की है। बालक श्री कृष्ण ने आततायी दैत्य शिरोमणि का वध कर डाला। पांच पांडवों ने मिलकर सौ कौरवों की सेना को परास्त करने का गौरव प्राप्त किया। कोई भी महापुरुष सफलता की ऊंचाईयों पर यकायक उड़ कर नहीं पहुंच गए थे। परिश्रम वही सार्थक हो सकता है, जब उसकी दिशा सही हो। स्टालिन, हिटलर तथा माओत्से तुंग के बारे में कहा जाता है कि वे युद्ध में विजय की अपेक्षा युद्ध की प्रक्रिया के प्रति चिंतित रहा करते थे। अपनी इसी चिंतन पद्धति के कारण उन्हें सफलता प्राप्त हो सकी। सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम चाहिए और परिश्रम को सार्थक करने के लिए संघर्ष। संघर्ष प्रकृति का नियम है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनुष्य सदा से संघर्ष करता रहा है फिर कोई सफलता इसका अपवाद कैसे हो सकती है? एक बीज ज़मीन पर उगने के लिए भूमि के कठोर परत से संघर्ष करता है। बारिश, पानी, ओले–तूफान से मुकाबला करता है, तब जाकर वह पुष्पित और पल्लवित हो पाता है। घर्षण द्वारा ऊर्जा की उपलब्धि के साथ विज्ञान का शुभारंभ हुआ और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हुए सभ्यता का विकास हुआ।

सफलता, अभ्यास, परिश्रम, स्वप्न, लगन, आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। ❑

IAS नामांकन प्रारंभ IAS
मुख्य परीक्षा-2004
प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा-2005
सफलता हमारी परंपरा है
सिविल सेवा परीक्षा में हमारे अंतिम रूप से चयनित छात्र

DEEPAK KR.
क्रमांक: 013539
प्रथम प्रयास में चयनित

RICHA
क्रमांक: 133940
प्राप्तांक: 325 (समाजशास्त्र)

PANKAJ S. SISODIYA
क्रमांक: 202681

KUMAR RAVI
क्रमांक: 063262

?
आप भी हो सकते हैं

समाजशास्त्र
BY
DR. S.S. PANDEY

द्वितीय बैच प्रारम्भ : 15 जुलाई
प्रथम दो कक्षा निःशुल्क
माध्यम
IAS STUDY CENTER
B-14, IIIrd FLOOR, COMMERCIAL COMPLEX,
NEAR BANK OF INDIA ATM, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
Ph.: 55484594, 9811923358

IAS

माध्यम

IAS STUDY CENTER

IAS

सफलता हमारी परंपरा है

इस परम्परा को कायम रखा है सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हमारे 12 प्रत्याशियों ने (19 प्रत्याशियों ने साक्षात्कार दिया था)।

हमारे संस्थान से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है– **कुन्दन कुमार –IAS (Roll No. 170474) HISTORY**

नामांकन प्रारंभ

मुख्य परीक्षा – 2004 / प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा – 2005

उपलब्द्ध विषय :

समाजशास्त्र एवं सामान्य अध्ययन

BY **DR. S.S. PANDEY**

दूसरा बैच प्रारम्भ : 15 जुलाई
प्रथम दो कक्षा निःशुल्क

DEEPAK KR.
क्रमांक: 013539
प्रथम प्रयास में चयनित

RICHA
क्रमांक: 133940
प्राप्तांक: 325 (समाजशास्त्र)

PANKAJ S. SISODIYA
क्रमांक: 202681

KUMAR RAVI
क्रमांक: 063262

इतिहास

द्वारा **रवि राकेश**
(Hindi & English Medium)

दूसरा बैच प्रारम्भ : 16 जुलाई
प्रथम दो कक्षा निःशुल्क

KUNDAN KR.
क्रमांक: 170474

He provided me the best guidance in History. His analytical ability and his approach to handle tricky question helped me a lot. I bet, you can also rely on him.

Kundan Kumar

दर्शन शास्त्र

BY **डा० देवेन्द्र विक्रम सिंह & PROF. K.N.P. SINGH**

दूसरा बैच प्रारम्भ : 15 जुलाई
प्रथम दो कक्षा निःशुल्क

ECONOMICS

BY **SHASHANK KOTHARI**
University Lecturer

दूसरा बैच प्रारम्भ : 16 जुलाई
प्रथम दो कक्षा निःशुल्क

G.S.

BY **NEERAJ SINGH & DR. S.S. PANDEY**

दूसरा बैच प्रारम्भ : 15 जुलाई
प्रथम दो कक्षा निःशुल्क

SANSKRIT by SHIVANAND SAHEB (Patna Univ.)

दूसरा बैच प्रारम्भ : 16 जुलाई, प्रथम दो कक्षा निःशुल्क

उ०प्र०लो०से० आयोग की 2001 बैच में भी हमारे संस्थान से 42 प्रत्याशियों का अंतिम रूप से चयन (54 ने साक्षात्कार दिया)

हमारी कार्य योजना–

- आपका नामांकन आपकी अंतिम सफलता तक।
- प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए समन्वित दृष्टिकोण।
- पूर्णतया परिमार्जित एवं परिवर्द्धित अध्ययन सामग्री।
- जाँच परीक्षा एवं अभ्यास पर अत्यधिक बल एवं समयबद्ध मूल्यांकन तथा दिशा–निर्देश।
- समय–2 पर लब्ध–प्रतिष्ठित विद्वानों एवं Toppers द्वारा दिशा–निर्देश एवं Motivation Classes

विशेष–

- पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध (Mains – Rs. 2500/- (P.T. – Rs. 2000/-
- SC/ST प्रत्याशियों को विशेष छूट छात्रावास का विशेष प्रबंध

Contact : B-14, IIIrd Floor, Commercial Comp. Near Bank of India ATM, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9, Ph.: 55484594

हौसले बुलंद हो तो अड़चनें बाधा नहीं बनती

○ बबीता रानी जायसवाल

तिनका–तिनका जोड़कर नीड़ बनाना, ईंट जोड़–जोड़कर घर बनाना और महिलाएं अपने बलबूते पर पुल बनाने की बात करें तो सहसा आपकी आंखें विस्मय से फटी रह जाएगीं। सचमुच यह बात आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन उसे हकीकत के धरातल पर उतारने में सफल हुई चितवादाग गांव की साहसी महिलाएं।

आदिकाल में माना जाता था कि स्त्री की कोमल कलाई सिर्फ चूड़ियों का ही बोझ उठा सकती है। पर आज कोई कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी न हो।

इक्कीसवीं सदी कि महिला आज किसी की मोहताज नहीं है। घर, परिवार या दफ्तर हर जगह अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा रही है। सामाजिक विकास में अब पुरुषों से किसी भी तरह से वह कम नहीं आंकी जाती।

झारखण्ड के गोविन्दपुर गांव की महिलाएं भी इसी श्रेणी में आती हैं जिन्होंने स्वयं व अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी पर मोहताज रहने के बजाय घर से बाहर कदम निकाला। अपने द्वारा किए गए कार्यों से यह साबित कर दिया कि पुरुष प्रधान समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वे नहीं कर सकतीं। फिर बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण की, ये महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। इस प्रकार के कार्य के लिए "स्वयं सहायता समूह" (एस.एच.जी.) के कार्य बहुत सराहनीय है।

यह ग्रामीण महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जिनकी स्थापना महिलाएं स्वयं करती है। हां, इस समूह की स्थापना में कुछ संस्थाएं इनका मागदर्शन अवश्य करती है। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) महिलाओं का एक ऐसा संगठन है, जिसमें अपने विकास के दरवाजे महिलाएं स्वयं खोलती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय वृद्धि, उत्पादन, जल प्रबंधन आदि से जुड़े विषय हों या फिर सामाजिक चेतना जगानी हो, अपने समूह के बल पर वे सारे क्रियाकलापों को बेहतर अंजाम देती हैं।

महिलाओं द्वारा स्वरोजगार – मशरूम उत्पादन स्वयं सहायता समूह, गोविन्दपुर (झारखंड)

इस संदर्भ में

रांची के चितवादाग गांव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कार्य प्रशंसनीय है। तिनका–तिनका जोड़कर नीड़ बनाना, ईंट जोड़–जोड़ कर घर बनाना और महिलाएं अपने बलबूते पर पुल बनाने की बात करें तो सहसा आपकी आंखें विस्मय से फटी रह जाएगीं। सचमुच यह बात तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन उसे हकीकत के धरातल पर उतारने में सफल हुई चितवादाग गांव की साहसी महिलाएं। इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि यदि हौसले बुलंद हो तो अड़चने कभी बाधा नहीं बन सकती।

कई बार निवेदन करने के बाद भी जब ब्लॉक आफिस के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो इन महिलाओं ने नदी के ऊपर पुल बनाने की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस बात का इंतजार नहीं किया कि गांव के पुरुष वर्ग कोई सकारा– त्मक कदम उठायेंगे। पुल जिसके अभाव में आवागमन को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डिजाइनिंग से लेकर निर्माण का सारा कार्य समूह की महिलाओं ने ही पूरा किया।

यहां तक कि ईंट, सीमेंट, बालू आदि जरूरी सामान लाने का कार्य भी इन्हीं लोगों ने किया। निर्माण कार्य में जितनी भी लागत आई उनका प्रबंध भी अपनी बचत योजना एवं लघु ऋण का कार्यक्रम चला रही संस्थाओं की मदद से किया।

स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख कार्य अपने सदस्यों को सहज वित्तीय सेवा यानी बिना झंझट के सस्ते दर पर कर्ज भी प्रदान करना है। चूंकि गांव में अक्सर लोगों को व्यवसाय के लिए ऐसे उधार की जरूरत होती है जो उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाए और जिसे आसान किस्तों में अदा किया जा सके। औपचारिक बैंकिंग सेवा इनकी जरूरतों का अच्छी तरह से समाधान नहीं कर पाती तो फिर इन्हें महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। इसलिए समूह के माध्यम से ये महिलाएं संगठित होती हैं ताकि ये बचत के रूप में अपने साधनों को एकत्रित कर सकें और बाहरी पूंजी प्राप्त करने की योग्यता पा सकें। ऐसे समूहों को बैंक अथवा विभिन्न संस्थानों से, जो लघु ऋण का कार्यक्रम चला रही है, उनसे सुविधा प्राप्त हो जाती है।

महिलाओं के इस समूह का प्रमुख उद्देश्य न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना एवं उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि इनकी यह भी कोशिश रहती है कि समाज में महिलाओं का स्तर ऊपर उठे उनमें कार्य करने से लेकर हर तरह के फैसले लेने की आत्मनिर्भरता आए आज स्थिति यह है कि वे न केवल घर–बाहर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है बल्कि कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी ले रही हैं और वे किसी भी तरह से किसी पर निर्भर नहीं हैं। ❑

STANDARD IX is where your child's future begins.

Do you see a budding engineer – or perhaps a doctor – in your ninth grader? Do you worry about his or her future? Public exams, college admissions, graduation, a career... the very thought of what lies ahead can be overwhelming.

No one understands that better than Brilliant. That is why our Professors have created two very special courses for Students of Stds. IX and X.

TARGET IIT ▲ MBBS

Target-IIT and Target-MBBS.
Firm beginnings for happy endings.

Brilliant's unique Target Courses are – as their names suggest – especially created for students whose long term aim is to try for Engineering or Medicine. They build, in each child, the foundation, the logical problem-solving approach, the confidence and the attitude so essential to succeed in difficult competitive exams. They pave a solid pathway for those who are serious about preparing for IIT-JEE or Medical Entrance, after Std. XII. And more importantly, they bring alive science and maths in a way that awakens and inspires the latent scientist – or doctor – in each child. This results, quite naturally, in better performance in the Std. X public exams.

To know more about Brilliant's Courses – Call, write, fax or e-mail

BRILLIANT® TUTORIALS

Your Gateway to Success

Box:4996 VPSR 12, Masilamani Street,
T. Nagar, Chennai 600 017.
Phone: 044-24342099, Fax: 044-24343829
e-mail:enquiries@brilliant-tutorials.com

BRILLIANT'S POSTAL COURSES OPEN FOR:
• IIT-JEE (2 Yr. Elite & 1 Yr. course)
• MBBS Ent. (2 Yr. CBSE & 1 Yr. course) • AIEEE/SEAT
• AMIE (I) (Sec. A & B) • MBA Ent. • MCA Ent. • GATE
• IAS • ESE • CSIR-UGC (NET) EXAM
• UGC (NET) EXAM (Humanities)
• GEOLOGISTS' EXAMINATION 2004 • GRE • TOEFL • BPOE

भूगोल

- द्वारा महेश कुमार बर्णवाल

(सिविल सेवा 1997 के सफल व्यक्ति व भूगोल : एक समग्र अध्ययन के लेखक)

अगला बैच - 5 जुलाई व 25 जुलाई

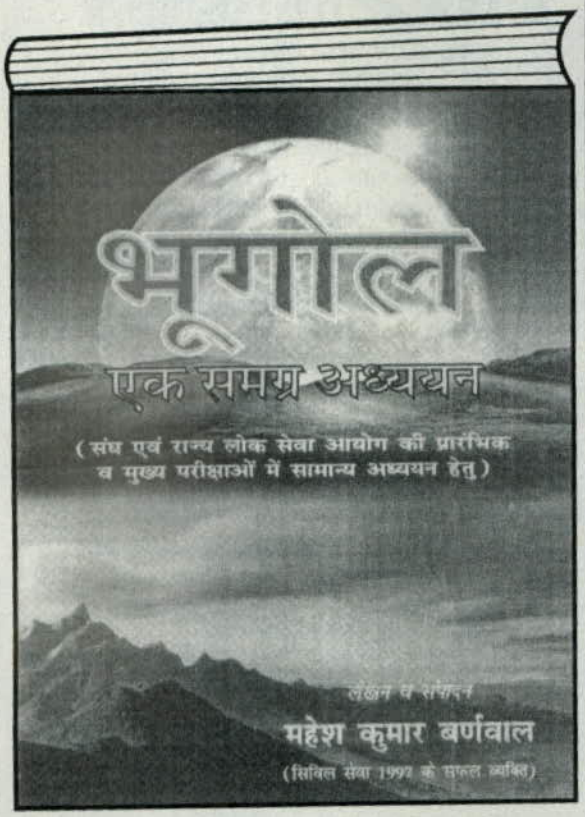

वितरक : मिश्रा बुक डिपो, दिल्ली; भार्गव बुक सेन्टर, इलाहाबाद; ज्ञान गंगा पब्लिकेशन राँची

(न मिलने पर सम्पर्क करें - 011-33304120)

भूगोल

(प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा)

पत्राचार पाठ्यक्रम

शुल्क

प्रारंभिक परीक्षा	रु. 1500/-
मुख्य परीक्षा	रु. 2500/-
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा	रु. 3500/-

विशेषताएँ

- लक्ष्यभेदी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री।
- छात्रों द्वारा हल कर भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों की जाँच की पूर्ण व्यवस्था।
- भेजे गए उत्तरों का पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण व संबंधित सुझाव।
- समय-समय पर टेस्ट परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था।
- प्रत्येक सप्ताह विशेष समस्या-समाधान सत्र।
- प्रत्येक माह तीन-दिवसीय विशेष कार्यशाला।
- परीक्षा के एक माह पूर्व एक सप्ताह की विशेष लक्ष्यभेदी कार्यशाला।

नोटः ड्राफ्ट *महेश कुमार बर्णवाल* के नाम से भेजें।

MERIDIAN COURSES
011-33304120, 011-27652131

B-13, IIIrd Floor (Above HDFC ATM)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

उपयोगी सहजन

○ जगनारायण

***भा**रतीय मूल की वनस्पतियों में सहजन ढेर सारी विशेषताओं से युक्त है। एक ओर जहां इस वृक्ष की ढेर सारी औषधीय उपयोगिताएं हैं, वहीं इसकी फली में पोषक तत्वों की प्रचुरता भी पाई जाती है।*

भारतीय मूल की वनस्पतियों में सहजन ढेर सारी विशेषताओं से युक्त है। एक ओर जहां इस वृक्ष की ढेर सारी औषधीय उपयोगिताएं हैं, वहीं इसकी फली में पोषक तत्वों की प्रचुरता भी पाई जाती है। सहजन की पत्ती, फल और फूल को सब्जी, रायता और सूप के रूप में नियमित प्रयोग करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

सहजन में पाए जाने वाले औषधीय गुण

सहजन में पाए जाने वाले औषधीय तत्वों के कारण यह अनेक रोगों में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। इसकी तासीर गर्म होती है जिससे इसमें उत्तम वीर्यवर्द्धक गुण पाए जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला लौह तत्व रक्तजनित विकारों में अत्यंत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। बढ़ी हुई तिल्ली वाले मरीजों के लिए सहजन काफी उपयोगी है। दुनिया के अनेक देशों में हुए शोधों से सहजन के विषय में ढेर सारे अन्य रोग निवारक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। अलग–अलग रोगों में सहजन के गुणकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं।

सहजन की फली

वात रोग में : आयुर्वेद में सहजन को वातनाशक के रूप में दर्शाया गया है। यह शरीर के जोड़ों जैसे– कमर, घुटनों के दर्द में उपयोगी है। वायु विकार में भी इसका प्रयोग रहता है। जोड़ों के दर्द में सहजन के फूल, पत्ती, फल और छाल सभी उपयोगी होते हैं। सहजन के तने की छाल का काढ़ा या पाउडर वातजनित रोगों में उपयोगी है। इसकी पत्तियों से निकाला गया रस शक्कर में मिलाकर कुछ समय नियमित प्रयोग करने से पेट का वायु गोला ठीक हो जाता है। पेट में गड़न होने पर इसकी पत्तियों का काढ़ा उपयोगी रहता है।

पाचन जनित विकारों में : सहजन में 4.8 प्रतिशत रेशा पाया जाता है, यह पाचन क्रिया को गतिशील बनाने वाला, आंतों की स्वच्छता में वृद्धि करने के साथ ही कब्ज और गैस जनित विकारों

को दूर करता है। बच्चों के दस्त और उल्टी में सहजन की पत्तियों का रस अत्यन्त लाभकारी होता है।

नेत्र रोगों में : सहजन में नेत्र रोगों के लिए जरूरी विटामिन 'ए' की मात्रा प्रत्येक 100 ग्राम में 4.07 मिलीग्राम पाई जाती है, जो आंतों में पहुंचकर 'प्रोया रेटिनाल' में बदल जाती है, जो नेत्रों के लिए श्रेष्ठ टॉनिक और उपयोगी तत्व है। इससे आंखों के अंधेपन, मोतियाबिंद और रतौंधी आदि रोगों से छुटकारा मिलता है।

गुर्दे व मूत्राशय की पथरी में : सहजन की पत्तियों की सब्जी बनाकर कुछ समय लगातार खाने से या इसके तने की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से गुर्दे व मूत्राशय की पथरी टूट–टूटकर स्वतः निकल जाती है। इससे पेशाब ज्यादा होता है जो मूत्र मार्ग की पथरी को साफ कर देता है।

हृदय के लिए उपयोगी : सहजन के फल, फूल, पत्ती और छाल में रक्त की धमनियों के विकास और फैलाव के गुण होते हैं। इसमें पाए जाने वाले उत्तेजनामूलक गुणों से रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। रक्त वाहिकाओं में जमा कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाता है, इससे हृदयाघात एवं पक्षाघात की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं।

ज्वर में उपयोगी : सहजन के फल–फूल एवं पत्तियों के काढ़े एवं सब्जी के रूप में प्रयोग से पसीना खूब आता है जिससे पेशाब खुल कर आता है और बुखार से राहत मिल जाती है।

गले के रोगों में : सहजन के तने की छाल का काढ़ा बनाकर उससे गरारा करने और इस छाल से रस निकालकर उसमें एक चौथाई शहद मिलाकर प्रयोग करने से गले के तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है।

बालों की रूसी में : सहजन की पत्तियों का रस निकालकर लगाने से बालों में रूसी समाप्त हो जाती है।

चर्म रोग में : इसकी जड़ को गोमूत्र के साथ पीसकर दाद और इसी तरह के अन्य चर्म रोगों में लगाने पर लाभ होता है।

फोड़े–फुंसी में : यदि फोड़े में मुंह बन जाने के बाद भी मवाद न निकल रहा हो, चुभन और दर्द हो रहा हो तो सहजन की पत्तियों की पुल्टिस बांधने से फोड़ा फूटकर बह जाता है और दर्द से राहत मिलती है।

सिर दर्द और मानसिक कमजोरी में : सहजन के फल और पत्तियों में फास्फोरस की पर्याप्त उपस्थिति के कारण सहजन मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता हैं। इसके प्रयोग से स्मरण शक्ति तथा मेधा का विकास और मानसिक रोगों के इलाज में फायदा होता है। ❑

IAS - PCS प्रीलिम तथा मेन्स
में सामान्य अध्ययन के लिए एक अपरिहार्य पुस्तक

भारतीय अर्थव्यवस्था
– सर्वेक्षण तथा विश्लेषण

द्वारा प्रो० एस० एन० लाल इ० वि०

पुस्तक को जिसने भी पढ़ा उसी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की

"--In Delhi the books of this standard that too in Hindi medium are really scarce. I am sure that this book and other books written by Prof. S.N. Lal will be of immense use to the candidates for civil services." (**Dr. Adesh Sharma,** Senior Teacher of Economics University of Delhi /Director, KALP Academy, Delhi)

''यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम्पटीशन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर लिखी गयी अकेली विश्वसनीय पुस्तक है जिसमें वह सबकुछ है जिसकी अपेक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में की जाती है। निश्चय ही यह अपने प्रकार की अकेली पुस्तक है''– विशाल विक्रम सिंह, Dy. SP., यूपी पी सी एस 2001 में 20वीं रैंक, पर चयनित।

पुस्तक प्राप्ति के कुछ प्रमुख स्थान– संस्करण– 2004, मूल्य– Rs. 130/

अजय पुस्तक केन्द्र यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद। मिश्रा बुक डीपो, आई. टी. ओ दिल्ली। नवशक्ति पुस्तक केन्द्र मुखर्जी नगर दिल्ली। आशीर्वाद, लखनऊ। जवाहर बुक डीपो, नयी दिल्ली। शिव पब्लिशिंग हाऊस, अलोपीबाग रोड इलाहाबाद, (प्रकाशक) – फोन :– 2508236

ECONOMICS
IAS कोचिंग के लिये PCS
उत्तर भारत का एकमात्र विश्वसनीय नाम
प्रो० एस० एन० लाल
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
बैच – 10 जुलाई 2004 से प्रारम्भ

सामान्य अध्ययन के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था
द्वारा डा० अनूप सिंह इ० वि०
सामान्य अध्ययन विषय विशेषज्ञों के द्वारा
सम्पर्क करें– (0532)2508617, 3154584
ला-MERIDIAN
लेबर चौराहा, अल्लापुर, इलाहाबाद

JIGISHA IAS ACADEMY

भावी प्रशासकों

आपकी सफलता की कामना करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि **जे.पी. सिंह के निर्देशन में जिगीषा आई. ए. एस. अकादमी** की स्थापना की गई है। संस्था की स्थापना इस दृढ़संकल्प के साथ की गई है कि...स्तरीय एवं कुशल मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

इस क्रम में लोक प्रशासन एवं सामान्य अध्ययन में उच्चतम गुणवत्ता के साथ हम उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में।

आइए हम अवगत कराते है आपको अपने पाठ्यक्रमों से।

लोक प्रशासन
द्वारा
जे. पी. सिंह

- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अन्तःविषयी दृष्टिकोण के आधार पर विश्लेषण ताकि प्रतियोगी न केवल विषय को समग्रता मे समझ सकें बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को भी समझ सके।
- साथ ही टॉपिक के पहलुओ पर आधारित अध्यापन ताकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में प्रतियोगी समर्थ हो।
- परम्परागत एवं सामयिक पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण विश्लेषण।
- प्रश्नोत्तर लेखन शैली पर विशेष बल।
- अद्यतन स्तरीय सम्पूर्ण नोट्स क्लास संस्कृति के भाग।
- प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत ध्यान देना तदनुसार सुधार कार्यक्रम लागू करना।

आइए... महसूस कीजिये...
अन्तर स्पष्ट एवं विशिष्ट है।

सामान्य अध्ययन
द्वारा
जे. पी. सिंह एवं टीम

- प्रत्येक खण्ड का विशेषज्ञतापूर्ण अध्यापन तथा खण्ड विशेष के प्रत्येक प्रकार के पहलुओं को स्पष्ट करना।
- प्रश्नोत्तर लेखन पर विशेष बल।
- अद्यतन स्तरीय नोट्स।
- प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत ध्यान तदनुसार सुधार कार्यक्रम लागू करना।
- समय-समय पर ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों का अतिथि व्याख्यान।

निःशुल्क कार्यशाला के साथ बैच प्रारम्भ

सामान्य अध्ययन.....17 जुलाई प्रातः 9.30 बजे

लोक प्रशासन.....18 जुलाई प्रातः 9.30 बजे

लोक प्रशासन एवं सामान्य अध्ययन में पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध।

हॉस्टल सुविधा उपलब्ध

जहाँ चाह... वहाँ राह...

The will to win IAS Exam

JIGISHA IAS ACADEMY

FLAT NO. 303, IIIrd Floor A 29-30, JAINA HOUSE COMM. COMPLEX DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9

Ph. 011-55175836 Cell. : 9810569158

जनसंख्या वृद्धि पर चिंता और चिंतन का दस्तावेज

पुस्तकः **जनसंख्या विस्फोट**; संपादकः **देवेन्द्र उपाध्याय**; प्रकाशकः **कल्याणी शिक्षा परिषद, 3320–21 जटवाड़ा, दरियागंज, दिल्ली–110002**; पृष्ठः **368**; मूल्यः **400 रुपये।**

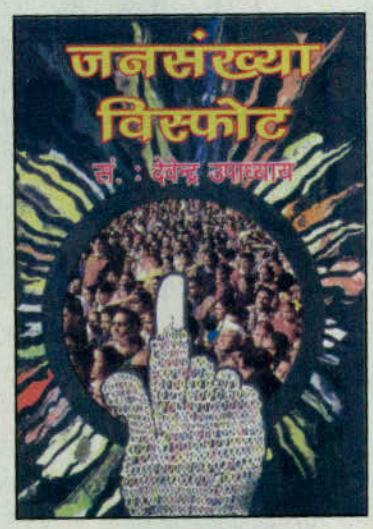

जनसंख्या हमारे देश की काफी पुरानी समस्या है और इस पर बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। फिर भी देवेंद्र उपाध्याय द्वारा संपादित पुस्तक 'जनसंख्या विस्फोट' में जनसंख्या के मुद्दे को इतनी गंभीरता और विस्तार के साथ संभवतः इसीलिए उठाया गया है कि भारतीय जनजीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करने वाले इस मसले के समाधान पर इन दिनों सरकारी तथा गैर–सरकारी स्तर पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना अपेक्षित है। 368 पृष्ठों के इस ग्रंथ को इस राष्ट्रीय समस्या को फिर से देश की प्राथमिकताओं में शामिल करने के ईमानदार प्रचारू रूप में देखा जा सकता है।

'जनसंख्या विस्फोट' में तथ्य भी हैं और विश्लेषण भी। आंकड़ें भी हैं और आंकड़ों को चुनौती देने वाले तर्क भी। आठ अध्यायों में विभाजित जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत चर्चा करते हुए इस समस्या से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे कि स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, मानव संसाधन, जन–जागरण, भ्रष्टाचार, राजनीति, धर्म आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का विस्तृत विश्लेषण इस पुस्तक में मौजूद हैं। यही नहीं, राज्यों, समुदायों तथा वर्गों के आधार पर जनसंख्या के नवीनतम और तुलनात्मक आंकड़ों के अलावा देश में जनगणना के इतिहास व प्रक्रिया के बारे में बड़ी रोचक और व्यापक जानकारी उपलब्ध है। साक्षरता और विकास के साथ जनसंख्या के संबंध को भी विस्तार से रेखांकित किया गया है। ये सभी तथ्य इस पुस्तक को जनसंख्या पर दस्तावेज का रूप देते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के उद्धरणों तथा तालिकाओं का साथ पाकर यह सामग्री अधिक विश्वसनीय और सुबोध बन जाती है।

पुस्तक में सामग्री यद्यपि व्यवस्थित और सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई है, पर इसकी विशेषता यह है कि समस्या का विश्लेषण विश्व के संदर्भ में किया गया है जिससे जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। इतने व्यापक फलक पर संपादित किए जाने के बावजूद इसमें जनसंख्या के सकारात्मक पहलुओं को स्पर्श नहीं किया गया है। जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए भले ही अभिशाप है और इस पर काबू पाना आवश्यक है, परंतु इसे एक शक्ति के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पक्ष की ओर यहां कोई संकेत नहीं है। इसके अलावा पुस्तक में निश्चित स्वरूप और दिशा का अभाव है। बहुत–सी सामग्री का स्रोत भी नहीं दिया गया है। फिर भी यह जनसंख्या जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक समस्या का एक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें विषय के हर पहलू की जानकारी, तथ्य एवं आंकड़ें एक ही जिल्द में उपलब्ध है। हिंदी में ऐसे विषयों पर प्रामाणिक सामग्री से युक्त पुस्तकों का वैसे भी अभाव है। अतः हिंदी जगत इस पुस्तक का खुले दिल से स्वागत करता है और संपादक से विकास से जुड़े अन्य विषयों पर भी ऐसी दस्तावेजी पुस्तकों की आशा करता है। ❑

(समीक्षक : सुभाष सेतिया)

IAS/PCS

आनन्द एकेडमी

- उत्तर भारत का सर्वाधिक सफल संस्थान
- गत वर्ष 19 चयन
- पुस्तकालय व छात्रावास सुविधा उपलब्ध
- प्रारम्भिक परीक्षा से साक्षात्कार तक पूर्णतया आपके साथ

सामान्य अध्ययन : आनन्द शुक्ला के कुशल निर्देशन में -

- ★ अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत कक्षायें भी उपलब्ध
- ★ अलग-अलग टॉपिक विषय विशेषज्ञों द्वारा
- ★ व्यक्तिगत मार्गदर्शन
- ★ मॉडल पेपर द्वारा अभ्यास

उपलब्ध वैकल्पिक विषय :

अर्थशास्त्र	:	आनन्द शुक्ला
इतिहास	:	भूपेन्द्र पाण्डेय
दर्शनशास्त्र	:	अरुण त्रिपाठी
समाजशास्त्र	:	एस० एस० परमार

बैच प्रारम्भ

नामांकन जारी

अर्थशास्त्र

JRF/NET का नया बैच

13/3, बन्द रोड, इलाहाबाद ● फोन : 0532-2466692, 9415254465

CIVIL SERVICES???

कुछ संस्थानों के पेशेवर रवैये से छात्रों की सफलता की दर पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ता है। **Pre-cum-mains** का दृष्टिकोण मुख्यतः **mains** पर ही जोर देता है। नतीजतन, **Pre.** पर छात्रों का कमजोर ध्यान उन्हें **Pre.** में ही असफल बना देता ह,। जिससे **mains** की पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। **Pre.** में एक - दो **Attempt** की असफलता अंततः उनमें गंभीर निराशा पैदा कर देती है।

आर्थिक व मानसिक रुप से कमजोर पड़ने के कारण छात्रों का **Pre.** के लिये पुनः कोचिंग कर पाना आर्थिक कारणों से संभव नहीं हो पाता कुछ संस्थानों के तथाकथित दावों व घोषणाओं के बावजूद वहां नामांकित छात्र जिन्हें कमजोर शिक्षण के कारण विवश होकर हटना पड़ा, वर्तमान में हमारे संस्थान में नामांकित हैं।

बदले हुए हालात में इन्हीं मुश्किलों के मद्देनजर संस्थान ने प्रारंभिक विषयों के चार महीनें के कोर्स में नामांकन हेतु इच्छुक छात्रों की फीस में भारी कटौती की है।

G.S. - Rs. 2000/-, Optional- Rs. 3000/-

उपलब्ध विषयः

- भूगोल (प्रारंभिक - मुख्य) - राजीव सौमित्र
- दर्शनशास्त्र (सिर्फ मुख्य) - डा० ए० के मिश्रा
- हिन्दी साहित्य - डा० मिश्रा एवं अन्य
- इतिहास (सिर्फ प्रारंभिक) - डा० ए० के० मिश्रा
- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक - मुख्य) - संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा
- निबंध - डा० एस० एस० पाण्डेय

एकमात्र संस्थान जो प्रारंभिक परीक्षा (भूगोल) में सफलता की पूरी गारंटी देता है, अन्यथा फीस वापस।

विशेष आकर्षण :- ✦ विषय चयन से संबंधित निःशुल्क मार्गदर्शनः-

सिविल सेवा के अभ्यर्थियों (विशेषकर हिन्दी माध्यम) के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है। विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अतः यहाँ के एक्सपर्ट (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन किया जाता है।

नोटः- इसके लिये कार्यालय में अंशुमन (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) से सम्पर्क कर समय निश्चित कर लें।

संस्थान के सलाहकार सदस्य : अजीत कुमार (IAS अधिकारी) एस० डी० तिवारी (PCS अधिकारी)

✦ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था ।
✦ SC/ST/OBC को फीस में 20% छूट।

अगला बैच 29 जुलाई से प्रारंभ

आरोहण IAS/PCS

(हिन्दी माध्यम का विश्वसनीय संस्थान)

पताः 204, दूसरी मंजिल, A -23, 24 सतीजा हाऊस (बत्रा सिनेमा हाल के पीछे), डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-9

Tel. : 011-27652362 (O), 0-9868259370

नामांकन अधिकतम 30

UNIVERSITY OF ALLAHABAD

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

ADMISSION TO ONE YEAR P.G. DIPLOMA COURSES IN

♦TOWN COUNTRY PLANNING ♦ TOURISM ADMINISTRATION ♦ CARTOGRAPHY AND SURVEYING

Eligibility : - Graduation in any discipline from any recognised university. The brochure -cum Application form can be obtained from and submitted in the **Geography Department** between **5th July, 2004 and August 18th , 2004** by paying Rs. 300/- in cash or by D. Draft of Rs. 350/-.

(1) For admission to diploma in Town - Country Planning the D. Draft should be in favour of **Course - co-ordinator, Town - Country Planning**;

(2) For admission to diploma in Tourism Administration the D. Draft should be in favour of **Course Co-ordinator Tourism Administration**; and

(3) For admission to diploma in Cartography & Surveying, the D. Draft should be in favour of **Course Co-ordinator, Cartography & Surveying**.

The D. Draft must be payable at Allahabad. For further details you may contact (i) on **Tel. 0532-2503094 & Mob. 9415367724** for *Town Country Planning*; (ii) **Dr. Satish Kumar Singh/Sri Ashwajeet Chaudhary** on **Mob. 9415364462**, for *Tourism Administration*, and (iii) on **Tel. 0532-2468311 & Mob. 9415368958** for *Cartography and Surveying programmes*, or log on www.allduniv.edu

Prof. B.N. Mishra
Course Co-ordinator
Town Country Planning
Geography Department
University of Allahabad

Prof B.N. Singh
Course Co-ordinator
Tourism Administration
Geography Department
University of Allahabad

Prof. M. Sinha
Course Co-ordinator
Cartography & Surveying
Geography Department
University of Allahabad

(पृष्ठ 35 का शेषांश)

कारण देश की आर्थिक स्थिति मानसून से प्रभावित हुआ करती है। इसीलिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने आर्थिक समीक्षा करते हुए कहा है कि "भारतीय कृषि मानसून में जुए का खेल है।"

वर्षा के अनियमित और असमय होने पर किसानों को लाभ की जगह हानि होती है। कृषि में वर्षा की मात्रा के साथ ही उसका वितरण काफी महत्वपूर्ण है। किसी साल की थोड़ी वर्षा भी भली प्रकार से वितरित होने पर अन्य साल की दुगुनी किंतु अनियमित रूप से हुई वर्षा से अच्छी रहती है। असमय हुई वर्षा से कृषि को बहुत हानि पहुंचती है। इससे कृषि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाते हैं।

मूलतः कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियां कृषि–उत्पादन से जुड़ी हैं। विकासशील आर्थिक व्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ ही अच्छे जीवनयापन की लालसा में खाद्य सामग्री की मांग भी बढ़ती जाती है, जिससे कृषि पर उत्तरोत्तर दबाव पड़ता है। स्वतंत्रता के पचपन वर्षों बाद भी कृषि–उत्पादन की बढ़ोत्तरी की दर तीन प्रतिशत के करीब है, जबकि आर्थिक विश्लेषण तथा अनुमान के आधार पर पांच प्रतिशत की सालाना दर होनी चाहिए। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा देसी खाद के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है। इस सुझाव से सहमत होते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने जल–प्रबंध के महत्व पर भी विचार किया है। उचित जल प्रबंधन के द्वारा कृषि–उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है।

कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए किए जा रहे अनेक उपायों से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। लेकिन इस संदर्भ में यह तथ्य भी उजागर है कि जल प्रबंधन, उर्वरकों का उपयोग तथा कृषि कार्य के नित नई तकनीकों के अपनाए जाने के बावजूद भारतीय कृषि की जलवायु पर निर्भरता बनी रहेगी। वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलते रहे हैं। फिर भी भारतीय कृषि की मानसूनी जल वर्षा पर निर्भरता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पिछले दशकों में भारतीय कृषि की पूर्ण निर्भरता को कम करने के प्रयास में कुछ सफलता मिली है। यह कार्य मौसम विज्ञान के द्वारा जल वर्षा के पूर्वानुमान से संभव हो सका है। इस साल मौसम विभाग के अनुसार मानसून पवन जल्द पहुंच रहा है, साथ ही यह अनुमान है कि मानसून की बरसात अच्छी होगी। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

स्वतंत्रता दिवस 2004, विशेषांक

स्वतंत्रता दिवस 2004 विशेषांक 'आम आदमी के लिए विकास' विषय पर केंन्द्रित होगा।

हमारे देश के सत्तर प्रतिशत से अधिक आम लोग गांवों और कस्बाई इलाकों में रहते हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना एक मुद्दा है। सामान्यतः इसका अभिप्राय बुनियादी क्षेत्र में, अर्थात कृषि, सिंचाई, वाटरशेड विकास में निवेश को बढ़ाना, कृषि ऋण और बीमा को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाना, ग्रामीण ढांचागत विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा पर बल देना, ग्रामीण बाजार और उद्यम खोलना, खाद्य संसाधन उद्योग का विकास कर कृषि उपज में मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहन देना आदि है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार–सृजन करना है ताकि गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके।

इस विशेषांक में योजना–प्रक्रिया के साथ ग्रामीण व्यवस्था के त्वरित जनोन्मुखी विकास को प्रोत्साहित करने के लिहाज से बहस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इस विषय पर प्रमुख विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और पत्रकार अपने सुविचारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

पाठक अपने आदेश स्थानीय एजेंट को अथवा विज्ञापन तथा प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड– IV, तल–7, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066 (दूरभाष : 26105590) को भेजें।

स्वतंत्रता दिवस 2004 विशेषांक का मूल्य रुपये 15/– है।

प्रो0 उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–
संपादक : राजेन्द्र राय

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

बाजार में उपलब्ध

मूल्य : 110/-

प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

नि:शुल्क
- भारत के हिन्दी भाषी राज्यों की Booklet
- भारत एवं विश्व के मानचित्र

प्रतियोगिता दर्पण की 'समसामयिक वार्षिकी' परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है विशेषकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में.

–पूनम कुमारी

44वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा (महिला संवर्ग) में सर्वोच्च स्थान पर चयनित

'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' का सामान्य ज्ञान की समसामयिक तैयारी में उत्कृष्ट योगदान रहा है.

– श्री कमल किशोर यादव

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान (OBC वर्ग में टॉपर) पर चयनित

तेरहवाँ पूर्णतः अद्यतन संस्करण 2004

मूल्य : 120.00 रुपए

अतिरिक्तांकों की सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का अंक है और शायद ही अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम का कोई विद्यार्थी ऐसा मिले जिसने यह न पढ़ा हो. प्रतियोगिता दर्पण की परीक्षोपयोगी सीरीज का कोई जवाब नहीं है.

–श्री अजय कुमार मिश्रा

सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान पर चयनित

टॉपर्स की राय

आठवाँ पूर्णतः अद्यतन संस्करण 2004

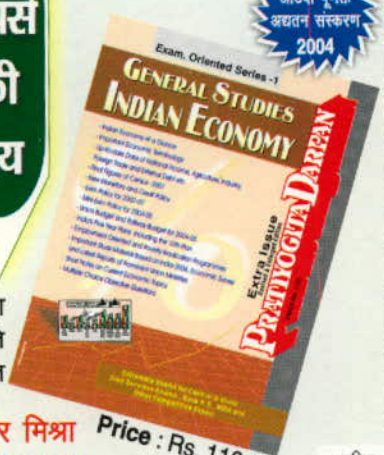

Price : Rs. 110.00

मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था एवं आधुनिक भारत व भारतीय कला एवं संस्कृति के अतिरिक्तांक पढ़े हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सहायक व परिपूर्ण हैं.

–श्री बिपिन कुमार मिश्रा

उ. प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2001 (परिणाम घोषित 2003) में सर्वोच्च स्थान पर चयनित

मुख्य आकर्षण

- भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं–एक दृष्टि में
- महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली
- राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण आदि के अद्यतन आँकड़े
- जनगणना-2001 के फाइनल आँकड़े
- नई मौद्रिक एवं साख नीति
- 2002-2007 के लिए निर्यात-आयात नीति
- 2004-2005 के लिए संशोधित मिनी निर्यात-आयात नीति
- 2004-2005 का केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट
- दसवीं पंचवर्षीय योजना सहित भारत की समस्त पंचवर्षीय योजनाएं
- भारत में संचालित रोजगारपरक एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम
- भारत-2004, आर्थिक समीक्षा तथा प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के नवीनतम प्रतिवेदनों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री
- सामयिक आर्थिक विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ
- महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

शीघ्र ही अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से सम्पर्क करें अथवा हमें 100 रु. का मनीऑर्डर भेजकर वी.पी.पी. द्वारा प्राप्त करें.

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 2530966, 2531101, 2602653
फैक्स : (0562) 2531940; E-mail : pratiyogita_darpan@sancharnet.in
फोन नं. : दिल्ली 23251866, 23251844, इन्दौर 2535892, पटना 2300932, लखनऊ 2637349, इलाहाबाद 2461043, चरखी दादरी (01250) 220120, जयपुर 2326019, देहरादून 2658555, रायपुर 2225851, रांची 2307374, मुम्बई 22075640